



चतुर्थ दिन
मां कूष्मांडा

मां कूष्मांडा को सृष्टि की आदिशक्ति माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, उन्होंने अपनी मद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। अष्टभुजा देवी सिंह पर विराजमान रहती हैं। इनकी पूजा से आरोग्य, ऊर्जा, समृद्धि और उत्साह प्राप्त होने की मान्यता है। भक्त जीवन में खुशहाली के लिए इनका आशीर्वाद मांगते हैं।

संक्षिप्त समाचार

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई रुकी

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई पर रोक लगा दी। यह केस 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए बयानों से जुड़ा है। मामला महाराष्ट्र की ट्रायल कोर्ट में चल रहा था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को बीच में

महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता एमएच श्रीश्रीमल को नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी के खिलाफ देशभर में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामलों की कुल संख्या 16 है।

इसमें से 15 मामले उन्होंने अपने 2024 के लोकसभा चुनावी हलफनामे में घोषित किए हैं, और 1 मामला पुणे में सावरकर परिवार द्वारा दायर किया गया है। राहुल ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 8 सितंबर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जारी समन रद्द करने से इनकार किया था। राहुल गांधी की ओर से वकील अभिषेक सिंघवी पेश हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला दिया। सिंघवी ने कहा कि इस मामले में कानून पहले ही स्पष्ट हो चुका है। हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता एमएच श्रीश्रीमल की याचिका पर गिरगांव मजिस्ट्रेट के 28 अगस्त 2019 के आदेश को बरकरार रखा था।

चीन ने लद्दाख की 28 जगहों को अपना बताया

बीजिंग/नई दिल्ली (एजेंसी)। चीन ने लद्दाख की 28 जगहों के नाम तय करने के भारत के फैसले पर आपत्ति जताई है। चीन ने मंगलवार को कहा कि ये इलाके उसके हैं और भारत के नाम बदलने या रखने से जमीन पर मालिकाना हक नहीं बदलेगा। भारत ने 2 अक्टूबर को इन जगहों के नाम अधिकारिक तौर पर तय किए थे। इनमें गोगरा और हॉट स्प्रिंग जैसे इलाके भी शामिल हैं, जहां 2020 में भारतीय और

चीनी सैनिकों के बीच तनाव हुआ था। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने मंगलवार को कहा कि चीन लद्दाख को भारत की ओर से बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश नहीं मानता। चीन ने भारत के इस कदम को गैरकानूनी बताते हुए कहा कि सीमा के पश्चिमी हिस्से के ये इलाके उसके हैं। माओ के मुताबिक, भारत के इस कदम से सीमा के पश्चिमी हिस्से में उन इलाकों पर चीन का दावा नहीं बदल सकता, जिन्हें वह अपना क्षेत्र मानता है। भारत के गृह मंत्रालय ने 2 अक्टूबर को लद्दाख की 28 जगहों और क्षेत्रों के नाम अधिकारिक तौर पर तय किए थे। भारत का फैसला 2023 में चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के नाम बदलने के जवाब में उठाया गया था। चीन अरुणाचल प्रदेश को 'जांगनान' यानी दक्षिणी तिब्बत कहता रहा है। भारत सरकार का कहना था कि उसका मकसद इन जगहों की पहचान को साफ करना है।

भारत ने दुनिया को सस्ती दवाएं और टैलेंट दिया

पीएम मोदी ने कहा-बदले में क्रेडिट-रॉयल्टी भी नहीं ली

देश पहली बार ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम का मेजबान



नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि सस्ती दवाओं से लेकर प्रतिभा तक, दुनिया भारत पर भरोसा करती है। भारत ने दुनिया को शून्य दिया, लेकिन कभी इसका श्रेय या रॉयल्टी नहीं मांगी। दिल्ली में पहली बार हो रहे ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में मोदी ने 25 मिनट स्पीच दी। कहा कि भारत की ताकत दूसरों को सक्षम बनाने में है। उन्होंने डिजिटल तकनीक, वैक्सीन सप्लाई, आर्थिक सुधारों और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भारत की भूमिका का जिक्र किया। तीन दिन का यह कार्यक्रम 15 अक्टूबर को खत्म होगा। इस साल फोरम की थीम 'बदलती दुनिया में ताकत के नए स्रोत तय करना' है।

सरकार का उद्देश्य नागरिकों को निर्भर बनाना नहीं- मोदी ने कहा- सरकार के पास अधिकार है, लेकिन उसका उद्देश्य अपने नागरिकों को व्यवस्था पर निर्भर बनाना नहीं होना चाहिए। बल्कि, उसका उद्देश्य अपने

नागरिकों को सशक्त और सशक्त बनाना होना चाहिए, और भारत इसी राह पर चल रहा है। पीएम बोले- भारत की 7.8 फीसदी ग्रोथ रही है। आज हमारा फॉरेन रिजर्व 700 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। भारत का कॉम्पिडेंस

ऊंचाई पर है। हमने इन्सॉल्वेंसी लॉ बनाया है। बिजनेस से जुड़ी छोटी-मोटी गलतियों को डिस्टेबिलाइज किया है। रिफॉर्म्स हमारा कन्विकशन है। पीएम ने कहा- इतिहास में अनेक वैश्विक संगठन बने।

उनके अपने-अपने हित रहे हैं। हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, लाइफस्टाइल फॉर एन्वायर्नमेंट जैसे इनीशिएटिव लिए। भारत किन विचारों को लेकर सामने आया, ये सबके सामने है। भारत जोड़ने और जुड़ने पर बल देता है। पावर दूसरों को एम्पावर करने के लिए ही है। भारत रिलायबिलिटी और स्टैबिलिटी की बात करता है। पीएम मोदी ने कहा- जब दुनिया को अफोर्डेबल मेडिसिन की जरूरत होती है, तब यह भारत से आती है। जब दुनिया को टैलेंट की जरूरत होती है, तब भारत के युवाओं पर भरोसा होता है। ये स्पष्ट है कि दुनिया को एक स्टीडी पिलर की जरूरत होती है, तब भारत अपना दायित्व समझते हुए हाथ आगे बढ़ाता है।

पीएम बोले- अवसर पैदा करें, देशों को जोड़े

ज्ञान, धन और शक्ति का महत्व इस बात में है कि उनका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाता है। भारत दूसरों के लिए अवसर पैदा करने और देशों को जोड़ने में विचारस रखता है। कोविड के दौरान भारत ने 100 से ज्यादा देशों में वैक्सीन पहुंचाई। भारत अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल पूरी मानवता के फायदे के लिए करना चाहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ सप्लाई चेन, ऊर्जा, खनिज और तकनीक भी देशों के बीच दबाव बनाने के साधन बन रहे हैं। दुनिया को भरोसेमंद साझेदारों की जरूरत है। सरकार का उद्देश्य लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना है। उन्होंने दावा किया कि पिछले एक दशक में भारत ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। स्टार्टअप के मौके छोटे शहरों तक पहुंचे हैं। आर्थिक सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की विकास दर 7.8 फीसदी रही और विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से ज्यादा है। कारोबार को आसान बनाना और सुधार करना सरकार की प्रतिबद्धता है।

आशुतोष रांका और सौरव दास जंतर-मंतर से गिरफ्तार

सरकार ने कल से ही यहां प्रोटेस्ट बैन किया, सीजेपी नेता प्रदर्शन पर अड़े



नई दिल्ली (एजेंसी)। कॉंकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका को मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। दोनों सीजेपी समर्थकों के साथ जंतर-मंतर पर पहुंचे और नारेबाजी कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने सभी को पकड़ लिया। सीजेपी ने हिरासत में लिए गए नेताओं का वीडियो जारी किया। रांका ने कहा, 'ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक प्रोटेस्ट जंतर-मंतर पर ही होगा। आज 10 लोग आए हैं, कल 1000 आएंगे, परसों 10,000 आएंगे। जंतर-मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं हो सकते। केंद्र सरकार ने सोमवार को इसे निर्धारित प्रदर्शन स्थल की लिस्ट से हटा दिया था। सीजेपी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर और एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन बुलाया था।

दीपके बोले- तिरंगा लहराना कब से वायलेशन होगया

सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा- तिरंगा लहराना कब से वायलेशन हो गया जो भी ये सोचता है तिरंगा लहराना जंतर-मंतर पर वायलेशन है, वो देशद्रोही है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे ही देश में, भारत देश में तिरंगा लहराना कानून का उल्लंघन कब से हो गया। यह तानाशाह मानसिकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। केंद्र सरकार ने सोमवार को जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की लिस्ट से हटा दिया था। सरकार ने 33 साल पहले जंतर-मंतर को प्रदर्शन की जगह तय किया था। यहीं पर अन्ना आंदोलन, पहलवानों का प्रदर्शन, कॉंकरोच पार्टी का धरना हुआ था। गृह मंत्रालय की बनाई कमटी की सिफारिश पर दिल्ली का रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और पूर्वी दिल्ली का ग्राउंड प्रदर्शन तय किए गए हैं। सरकार ने इसे हटाने के पीछे की वजह नहीं बताई है। माना जा रहा है कि संसद से सिर्फ 1.5 किमी दूरी इसकी वजह है। सीजेपी नेता दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे थे।

बड़ा फैसला! यूपीआई पर 0.4 फीसदी चार्ज दीवाली तक टला

त्योहारी सीजन को देखते हुए मोदी सरकार ने लिया बड़ा निर्णय 2 हजार से ज्यादा के पेमेंट पर 15 अक्टूबर से होना था लागू

नई दिल्ली (एजेंसी)। यूपीआई पेमेंट पर 15 अक्टूबर से लागू होने वाला चार्ज दीवाली तक टाल दिया गया है। इसमें दुकानदार को 2,000 से ज्यादा का यूपीआई पेमेंट करने पर 0.4 फीसदी चार्ज लगना था। आम लोगों के बीच ट्रांजेक्शन पहले की तरह फ्री रहेगा। एनपीसीआई ने त्योहारी सीजन को देखते हुए इसे टालने का फैसला किया है। एनपीसीआई ने कहा है कि इसे दीवाली के तुरंत बाद लगाया जाएगा, लेकिन अभी तारीख नहीं बताई है। अगर ग्राहक दुकानदार को 2,000 से ज्यादा का यूपीआई पेमेंट करता है, तो दुकानदार को कुल रकम पर 0.4 फीसदी का एमडीआर चार्ज देना होगा। अगर ग्राहक 75,000 या उससे ज्यादा का बड़ा पेमेंट करता है, तो प्रतिशत के बजाय अधिकतम फ्लैट चार्ज लागू होगा।

देशभर में हुआ था यूपीआई पर चार्ज का विरोध- सरकार के इस फैसले का देशभर के कारोबारियों और विपक्षी नेताओं ने विरोध किया था। विरोध दो स्तरों पर हुआ। विपक्षी नेताओं ने राजनीतिक और आम लोगों पर असर को लेकर सवाल उठाए, जबकि कारोबारी संगठनों ने लागत बढ़ने और ग्राहकों पर बोझ पड़ने की आशंका जताई। उनका कहना था कि इससे छोटे कारोबारियों को ज्यादा नुकसान होगा।

एसआईआर के खिलाफ

विपक्ष की याचिका में 14 खामियां

सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने बताया-कोर्ट फीस 220 रुपए कम दी

पेज भी गायब, मल्लिकार्जुन खड़गे का आईडी कार्ड धुंधला

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत 11 विपक्षी नेताओं की ओर से दायर एसआईआर याचिका में करीब 14 खामियां बताई हैं। यह याचिका एसआईआर में बड़े पैमाने पर नाम हटाने और गड़बड़ियों के आरोपों से जुड़ी है। इन खामियों के कारण मंगलवार को याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, रजिस्ट्री ने याचिका के साथ जमा किए गए दस्तावेजों में भी खामियां बताईं। कुछ पन्ने पढ़ने लायक नहीं हैं, जबकि कुछ पन्ने गायब हैं। इसके अलावा, कोर्ट फीस भी 220 रुपए कम जमा की गई है।



रजिस्ट्री ने कुल 14 खामियां दर्ज की हैं। रजिस्ट्री ने कहा है कि याचिका दाखिल करने वाले वकील से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन

राहुल बोले- ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लेकर रहेंगे, जितना समय लगे, आंदोलन जारी रहेगा

एसआईआर के खिलाफ और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर इंडी ब्लॉक के नेताओं ने राहुल गांधी के घर चाय पर बैठक की। करीब दो घंटे चली इस बैठक के बाद सभी नेता एक साथ बाहर आए और मीडिया को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लेना हमारा मिशन है।

खड़गे के पहचान पत्र (आईडी कार्ड) की साफ कॉपी मांगी है। इसके अलावा, 9 याचिकाकर्ताओं से याचिका दायर करने के लिए लिखित सहमति भी मांगी है। 12 अक्टूबर को दायर याचिका में भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्तों को पक्षकार बनाया गया है।

मार्च के खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज

सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने के मामले में दिल्ली पुलिस ने 4 एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, ये केस कर्नाट प्लेस, बाराखंबा रोड, तिलक मार्ग और मंदिर मार्ग थाने में दर्ज किए गए हैं। राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी नेता सोमवार को याचिका दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करके पहुंचे थे। याचिका में रियरयर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति बनाने की मांग की गई है। इसमें तकनीकी विशेषज्ञों और प्रतिष्ठित नागरिकों को भी शामिल करने की मांग है। याचिका में कहा गया है कि यह समिति तय समय के भीतर एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों और किए गए बदलावों का स्वतंत्र ऑडिट करे।

आसमान पर सेंसेक्स 1100 अंक तक उछला

शेयर मार्केट की बुल रफतार, बम-बम रहा बाजार

नई दिल्ली (एजेंसी)। घरेलू शेयर बाजार में गजब की तेजी दिखी है। मार्केट बंद के दौरान 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1109.10 अंक यानी कि 1.54 फीसदी बढ़त के साथ रहे



निशान में 73,033.78 पर बंद हुआ। वहीं, 50 शेयरों निफ्टी 358.60 अंक यानी कि 1.60 फीसदी चढ़कर 22,721.95 पर बंद हुआ। मार्केट बंद के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में

से 27 में तेजी और सिर्फ तीन शेयरों में गिरावट दिखी। इनमें टॉप गेनर एचसीएल टेक में 8.28 फीसदी की तेजी और टॉप लुजर कोटक महिंद्रा बैंक में 0.90 फीसदी की गिरावट दिखी। मार्केट की इस बढ़त में निवेशकों की संपत्ति में करीब 3 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इस बीच सेंसेक्स पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप बढ़कर अब 469 लाख करोड़ रुपये हो गया है। बीते कारोबारी सत्र यानी कि 12 अक्टूबर सोमवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला था, जबकि इसकी क्लोजिंग गिरावट के साथ हुई थी। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 400 अंकों की तेजी के साथ 72,771.32 पर खुला था, लेकिन जब बंद हुआ तो यह अपने डे हाई से करीब 950 अंक लुढ़क गया।

लंगूर के हमले से कोमा में गए बच्चे की एम्स में मौत



यमकेश्वर। टांगर गांव में लंगूर के झपटा मारने के बाद गिरकर कोमा में गए शिवांशु (11) की एसएस् ऋषिकेश में इलाज के दौरान मौत हो गई। क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। टांगर गांव में शुक्रवार को एक लंगूर ने शिवांशु पर अचानक झपटा मार दिया था, जिससे वह गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजनों ने उसे एसस् ऋषिकेश में भर्ती कराया था। वह कोमा में चला गया था। परिजनों ने बताया डॉक्टरों ने उसके दिमाग में खून का थक्का बनने की बात कही थी। इलाज के दौरान सोमवार देर रात शिवांशु ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने बताया कि लंगूर काफी समय से गांव में डेर जमाए हुए हैं शिवांशु पर झपटा मारने वाले लंगूर को ट्रैकुलाइज करने के लिए लैसडीन वन प्रभाग के एसडीओ सुधीर कुमार के नेतृत्व में टीम ने सोमवार और मंगलवार को सचें ऑपरेशन चलाया लेकिन लंगूर नहीं मिला। लालबाग रेंज के वन क्षेत्राधिकारी अनुराग जोशी ने बताया कि बुधवार को भी लंगूर को ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। उसे ट्रैकुलाइज करने के लिए अतिरिक्त दवा मंगवाई गई है।

ओवैसी का समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत गढ़ पर अटैक

आजमगढ़ को कमी मुलायम सिंह यादव ने बनाया था अमेठा!

लखनऊ/आजमगढ़ (एजेंसी)। हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नौ दिनों तक इंतजार किया और फिर समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सपा ने यूपी विधानसभा चुनावों में तालमेल के उनके खुले ऑफर को ठुकराया तो ओवैसी ने भी जैसे उनकी बार उनकी चुनौती जड़ें ही उखाड़ने की ठान ली है। असदुद्दीन ओवैसी ने सपा और अखिलेश यादव को टारगेट करने के लिए सबसे पहले आजमगढ़ को चुना है, जिसे मुलायम सिंह यादव ने तीन दशकों से ज्यादा समय तक अपना अभेद्य किला बनाकर रखा था। एआईएमआईएम एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के मुसलमानों से कहा है कि वे यादव परिवार की लाल टोपी की गुलामी करना बंद कर दें। ओवैसी ने यह आह्वान आजमगढ़ की सभा में किया, जिसे सपा का गढ़ माना जाता है।



मुस्लिम नेतृत्व की बात कहकर सपा को चुनौती- आजमगढ़ में जाकर ओवैसी का यह कहना कि मुसलमान अब नेता बनने की तैयारी करें, क्योंकि उन्होंने जिन दलों के लिए सीढ़ियां लगाई, उन्होंने कभी भी उन्हें उनका वाजिब हक नहीं दिया। इसके लिए उनके निशाने पर सपा ही नहीं, बसपा और कांग्रेस है। असदुद्दीन ओवैसी का आरोप है कि यूपी के मुसलमानों ने मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव की खिदमत में पीढ़ियां लगा दी, लेकिन उन्होंने किसी मुसलमान को प्रमुख नेता बनने का मौका नहीं दिया।

संपादकीय

गुटखा और तंबाकू पर प्रतिबंध

उत्तराखंड में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू युक्त खाद्य उत्पादों पर अगले 1 वर्ष तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध का उद्देश्य केवल बाजार से कुछ उत्पादों को हटाना नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता को गंभीर बीमारियों से बचाना और आने वाली पीढ़ी को नशे की गिरफ्त में जाने से रोकना भी है। यह आदेश खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखकर जारी किया गया है। हालांकि, इसकी सफलता का वास्तविक आकलन तभी हो सकेगा, जब प्रतिबंध के त्रिमान्वयन और उसके परिणामों से जुड़े आंकड़े सामने आएंगे।

तंबाकू का सेवन मुंह के कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ाता है। गुटखा और तंबाकू युक्त उत्पादों का इस्तेमाल विशेष रूप से युवाओं के भविष्य के लिए चिंता का विषय है। कम उम्र में शुरू हुई ऐसी आदत धीरे-धीरे लत का रूप ले सकती है और व्यक्ति की सेहत के साथ-साथ परिवार की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकती है। प्रतिबंध से इन उत्पादों की खुली बिस्त्री पर अंकुश लगाने, उनकी उपलब्धता घटाने और समाज में तंबाकू के दुष्प्रभावों को लेकर जागरूकता बढ़ाने का अवसर मिलता है। किसी भी कानून की वास्तविक परीक्षा उसके आदेश में नहीं, बल्कि उसके जमीन पर लागू होने में होती है। उत्तराखंड में वर्ष 2013, 2015 और 2019 में भी ऐसे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जा चुके हैं। यदि प्रतिबंध प्रभावी रहा होता, तो बार-बार नए आदेश जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ती? प्रतिबंध को सफल बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग, पुलिस, जिला प्रशासन और स्थानीय निकायों के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। एक बड़ी चुनौती यह भी है कि प्रतिबंधित उत्पादों को अलग-अलग नामों से बेचा जा सकता है या तंबाकू और पान मसाले को अलग-अलग पैकेटों में उपलब्ध कर-कार नियमों से बचने की कोशिश हो सकती है। केवल दुकानों पर छापे मारना पर्याप्त नहीं है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो लोग तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, उन्हें परामर्श और आवश्यक चिकित्सा सहायता आसानी से मिले। गुटखा और तंबाकू उत्पादों के पाउच सार्वजनिक स्थानों, नालियों और सड़कों पर गंदगी बढ़ाते हैं। इनकी बिस्त्री में कमी आने से कचरे का बोझ घटाने में भी मदद मिल सकती है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिबंधित वस्तुओं का अवैध कारोबार न पनपे। यदि निगरानी कमजोर हुई, तो अवैध आपूर्ति बढ़ सकती है और उपभोक्ताओं को सस्ते या बिना गुणवत्ता नियंत्रण वाले उत्पाद मिलने का जोखिम पैदा हो सकता है। उत्तराखंड में गुटखा और तंबाकू युक्त खाद्य उत्पादों पर प्रतिबंध जनस्वास्थ्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार को नियमित रूप से यह सार्वजनिक करना चाहिए कि कितनी दुकानों और गोदामों का निरीक्षण हुआ, कितनी अवैध खेप पकड़ी गई, कितने मामलों में कार्रवाई हुई और तंबाकू छोड़ने के लिए कितने लोगों को सहायता मिली। इससे प्रतिबंध की वास्तविक प्रभावशीलता का आकलन संभव होगा। कानून बनाना सरकार का दायित्व है, लेकिन उसे प्रभावी बनाना पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी है। गुटखा और तंबाकू पर प्रतिबंध की असली सफलता तब मानी जाएगी, जब दुकानों से इनकी उपलब्धता घटने के साथ लोगों की निर्भरता भी कम होगी और आने वाली पीढ़ी को तंबाकू-मुक्त जीवन का बेहतर विकल्प मिलेगा।



सुनील कुमार महला

आज विज्ञान और तकनीक का युग है। विज्ञान और तकनीक के इस दौर में मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीविजन, चार्जर, बैटरी, प्रिंटर और अन्य विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन जब ये उपकरण पुराने हो जाते हैं या काम करना बंद कर देते हैं, तो इनसे ई-कचरा पैदा होता है। गौरतलब है कि खराब मोबाइल फोन के अलावा पुराने इंडरफोन, यूएसबी केबल, रिमोट, खिलौने, छोटे पंखे और बिजली से चलने वाले अन्य उपकरण भी ई-कचरे में शामिल हैं। आज धरती पर ई-कचरे की मात्रा लगातार बढ़ रही है और यह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। कहना गलत नहीं होगा कि यदि इन उपकरणों का समय पर सही तरीके से निपटान नहीं किया जाए, तो ये मिट्टी, पानी, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकते



मनोज कुमार अग्रवाल

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देश भर में और दिल्ली में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का दौर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है।मतदाता सुचियों के स्पेशल ईईटसिव रिवीजन और कथित तौर पर योग्य मतदाताओं के नाम सूची से हटाने को लेकर विवाद है।सोमवार को इंडिया ब्लाक ने कनाटपलेस से सुप्रीम कोर्ट तक एक विरोध मार्च भी निकाला और चीफ जस्टिस से मिलने का प्रयास किया।चीफ जस्टिस ने मामला अदालत में विचाराधीन होने का हवाला देते हुए इस पर अदालत से बाहर मिलना चर्चा करना न्यायिक मर्यादा के खिलाफ बताया। चुनाव आयुक्त सुखदेव सिंह संघु और विवेक जोशी द्वारा पिछले कुछ महीनों में एसआइआर प्रक्रिया से जुड़े फैसलों पर आपत्ति जताए जाने की खबरें सामने आई थीं।विपक्ष और विभिन्न संगठन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। इंडिया ब्लॉक द्वारा संसद से सुप्रीम कोर्ट तक विरोध मार्च निकाला गया है, जिसमें राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता शामिल हुए हैं। दिल्ली में संसद भवन और जंतर-मंतर के पास ठरक ठरक अन्य संगठनों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है।

ई-कचरा: आधुनिक युग की एक गंभीर पर्यावरणीय चुनौती

हैं। बहरहाल, पाठकों को बताता चलूं कि पुराने और बेकार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सुरक्षित निपटान, पुनर्चक्रण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 14 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय ई-कचरा दिवस मनाया जाता है। वास्तव में, इस दिवस को मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि पुराने मोबाइल, छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, केबल और बैटरी को सामान्य कूड़े में फेंकने के बजाय उचित संग्रह केंद्रों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि उनका सुरक्षित पुनर्चक्रण किया जा सके। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी। इसकी शुरुआत अपशिष्ट विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फोरम ने की थी। वास्तव में, यह एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन है, जो विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक कचरे के उचित प्रबंधन और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस संगठन की स्थापना वर्ष 2002 में बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हुई थी। हाल फिलहाल, इसमें कोई संदेह या दोराय नहीं है कि विज्ञान और तकनीक ने हमारे जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाया है, लेकिन इनसे जुड़े उपकरणों का गलत तरीके से निपटान पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या बन सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे में सीसा और पारा जैसे हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं, जो मिट्टी और पानी को दूषित कर सकते हैं। दूसरी ओर, इसी कचरे में सोना, तांबा और प्लैटिनम जैसी कीमती धातुएं तथा कई उपयोगी पदार्थ भी पाए जाते हैं, लेकिन इन पदार्थों को

पुनर्चक्रण के माध्यम से दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। इससे जहां एक ओर प्राकृतिक संसाधनों की बचत होती है, वहीं पर नए कच्चे माल(रा-मैटिरियल) की आवश्यकता कम होती है। ई-कचरे को खुले में जलाने या असुरक्षित तरीके से तोड़ने से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। इसलिए देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अधिकृत संग्रह केंद्रों या पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं तक पहुंचाए और मनुष्यों, अन्य जीवों तथा प्रकृति के स्वास्थ्य की रक्षा में योगदान दे।

ई-कचरे की स्थिति:- विश्व और भारत-

संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट-2024 के अनुसार, वर्ष 2022 में दुनिया भर में लगभग 62 मिलियन टन यानी 6.2 करोड़ टन ई-कचरा उत्पन्न हुआ। वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति औसतन 7.8 किलोग्राम ई-कचरा पैदा हुआ। चिंताजनक बात यह है कि कुल ई-कचरे में से केवल 22.3 प्रतिशत का ही औपचारिक रूप से संग्रह और पुनर्चक्रण किया गया। शेष लगभग 77.7 प्रतिशत ई-कचरे का उचित प्रबंधन नहीं हो सका और उसका बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रों या कचरा भराव स्थलों तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, आज हमारा देश भारत भी ई-कचरे की समस्या से गंभीर रूप से प्रभावित है। दुनिया में चीन और अमेरिका के बाद भारत को ई-कचरा उत्पन्न करने वाले प्रमुख देशों में तीसरे स्थान पर बताया जाता है। भारत में ई-कचरे की मात्रा के संबंध में लगभग 4.5 मिलियन टन यानी 45 लाख टन प्रतिवर्ष का आँकड़ा

सामने आया है। उल्लेखनीय है कि हमारे देश में ई-कचरे का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कबाड़ी और अन्य लोगों द्वारा संसाधित किया जाता है। उपलब्ध अनुमानों में यह हिस्सा लगभग 80 से 90 प्रतिशत तक बताया गया है। इस काम में सुरक्षा के उचित उपाय नहीं अपनाए जाने पर काम करने वाले लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। ई-कचरे की बढ़ती मात्रा इस समस्या को और गंभीर बना रही है। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2010 से 2022 के बीच ई-कचरे में हुई वृद्धि की दर उसके औपचारिक संग्रह और पुनर्चक्रण की वृद्धि दर से लगभग पाँच गुना अधिक रही। ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर-2024 के अनुमान के अनुसार, यदि यही स्थिति बनी रही, तो वर्ष 2030 तक दुनिया में ई-कचरे की मात्रा बढ़कर लगभग 82 मिलियन टन यानी 8.2 करोड़ टन प्रतिवर्ष हो सकती है।

ई-कचरा कम करने के लिए क्या करें?

भारत जैसे तेजी से डिजिटल होते देश में मोबाइल फोन, कंप्यूटर, घरेलू उपकरणों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। इसलिए ई-कचरे को केवल सफाई की समस्या मानना उचित नहीं है। यह पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों की बचत, जनस्वास्थ्य और जिम्मेदारी के साथ उपभोग करने से जुड़ा विषय है। वास्तव में, ई-कचरे को कम करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल सोच-समझकर करना चाहिए।

वोट चोरी के आरोप:राजनीतिक अस्थिरता फैलाने का षडयंत्र

मुंबई के शिवाजी पार्क और अन्य हिस्सों में भी आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे सहित विभिन्न राजनीतिक दलों और समूहों ने प्रदर्शन किया है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया और नए कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में को वारंटों याचिका भी दायर की गई है। बढ़ते विरोध के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कुछ चुनावी दौर स्थगित किए गए हैं और चुनाव आयोग के अधिकारियों को सुरक्षा बढ़ाई गई है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जिस तरह आक्रामकता दिखा रहा है वह लोकतांत्रिक मर्यादों का उल्लंघन करने जैसा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के त्यागपत्र की मांग को लेकर धरना व रोष प्रदर्शन कर रही कांंग्रेस जनता पार्टी और इससे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा एसआइआर के विरोध में निकाला रोष प्रदर्शन और वोट चोरी का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति से मिलकर ज्ञानेश कुमार विरुद्ध कार्रवाई की मांग करने के बीच देश के 124 पूर्व आई.ए.एस., आई.एफ.एस. व आई.पी.एस. तथा अन्य सेवाओं से जुड़े अधिकारियों ने भी देश के जनसाधारण के नाम एक खुला पत्र लिखा है जिस में चुनाव आयोग और मतदाता सूची के विशेष गहन निरीक्षण का समर्थन किया गया है। पत्र में उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का आकलन राजनीतिक जुड़ाव के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी चुनाव आयोग के तहत केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा ने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड और जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनावों में हार का सामना किया है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा अपना पूर्ण बहुमत खो बैठी थी। उस समय चुनावी प्रक्रिया पर जीतने वाले पक्ष ने कोई शिकायत नहीं की थी। भारत सरकार के पूर्व सचिवों, राजदूतों, पुलिस महानिदेशकों, तथा अन्य संगठनों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है।

कहा कि चुनावी प्रक्रिया में गलतियों को सुधारा जाना चाहिए लेकिन इससे एसआइआर की वैधता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। एसआइआर का उद्देश्य अपात्र मतदाताओं को हटाना है। इस प्रक्रिया में कुछ अशुविधा हो सकती है, लेकिन यह भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। बूथों पर कब्जे, मतपेटियों में अपने पक्ष में मतपत्र ठूसने और चुनावी हिसा के दौर से भारत के बदलाव का जिक्र करते हुए अधिकारियों ने कहा कि आज की चुनावी व्यवस्था में कई स्तरों पर जांच और सुरक्षा उपाय हैं। इनमें मतदान एंजेंट, ईवीएम को सील करना, स्ट्रॉंग रूम की सुरक्षा और वीवीपैट से सत्यापन शामिल हैं। उन्होंने पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव का हवाला दिया, जिसमें दोबारा मतदान की नौबत नहीं आई और 1951 के बाद सबसे अधिक मतदान दर्ज किया गया। पूर्व अधिकारियों ने एसआइआर को मतदाता सूची को दुरुस्त करने और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने की आवश्यक प्रक्रिया बताया। उन्होंने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि इस प्रक्रिया के दौरान लगभग 22 लाख मृत मतदाताओं और सात लाख दोहरी प्रविष्टियों की पहचान की गई। पूर्व अधिकारियों ने कहा- हम किसी दल से नहीं जुड़े हैं। हम इसलिए पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि बिना पयोगी सुबूतों के चुनावों को बार-बार धांधलीपूर्ण बनाने से लोकतंत्र के प्रति जनता का विश्वास कमजोर होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एसआइआर किसी को मतदाता सूची से बाहर करने का हथियार नहीं है। मसीदा मतदाता सूची अस्थायी होती है और इसमें नाम न होने का मतलब नाम काटा जाना नहीं है। नोटिस और सुनवाई के बिना किसी का नाम नहीं हटाया जाता। पूर्व अधिकारियों ने कहा कि लोकतंत्र उन लोगों से कमजोर होता है, जो बिना सुबूत के पॉलीटिकल नैरेटिव गढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि यह साफ तौर पर चुनावी व्यवस्था के जरिये लोगों द्वारा खारिज किए जाने के बाद प्रासंगिक

बने रहने की कोशिश है। गौरतलब है कि इससे पूर्व 42 पूर्व न्यायाधीशों ने चुनाव आयोग के समर्थन में खुला पत्र लिखा था। सीजेपी और विपक्षी दलों के नेता देश की व्यवस्था को कमजोर करने व देश की साख व छवि को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, यह देश हित में नहीं है। एक लोकतांत्रिक सरकार जो देश के संविधान अनुसार काम कर रही है उसके प्रति भ्रम व भ्रांतिया पैदा करना लोकतंत्र के हित में नहीं है। विपक्षी दलों को जहां अपनी कमजोरियों के लेकर आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, वहीं भाजपा व मोदी सरकार की नीतियों से भी सीखने की आवश्यकता है। विपक्षी दल जिस तरह देश में एक नकारात्मक राजनीति माहौल बनाकर स्थापित सरकार व व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है, उससे देश में अराजकता का माहौल बनेगा जो आम आदमी सहित किसी के भी हित में नहीं होगा। सरकार की नीतियों का विरोध करना विपक्षी दलों का अधिकार है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करना जिसके वह स्वयं एक महत्वपूर्ण अंश हैं, अनुचित है। धरने व प्रदर्शन विपक्षी दलों की हताशा की दशाते ही हैं, साथ में जन साधारण की रोजमर्रा की जिंदगी में भी अनेक प्रकार की बाधाएं पैदा करते हैं। भीड़तंत्र को लोकतंत्र पर हावी नहीं होने दिया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो यह स्थिति अराजकता वाली ही होगी तथा जिस की लाठी उसकी भैंस वाली जंगल राज स्थापित होगा, भारत विरोधी शायद यही चाहते हैं। सवाल यह है कि काकाचोर पार्टी को आगे कर क्या विदेशों से संचालित भारत विरोधी ताकतें भारत में राजनीतिक अस्थिरता फैला कर भारत को कमजोर करने के मंस्बू को कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्षी दल इस में सहयोगी बन कर अपने हाथ धोने की कोशिश कर रहा है। यह बेहद शर्मनाक और खतरनाक अजेंडा है इस को हर कीमत पर नकारना होगा।

आन्दोलन वही, जो सार्थक मुद्दा, दिशा एवं भरोसे से जुड़ा हो

ललित गर्ग

आज सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि जनांदोलनों की दिशा कौन तय कर रहा है? क्या आंदोलन वास्तव में जनसमस्याओं के समाधान के लिए खड़े हो रहे हैं, अथवा जनता के असंतोष को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का साधन बनाया जा रहा है? यह प्रश्न किसी एक दल या संगठन तक सीमित नहीं है।

लोकतंत्र में असहमति उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी जीवंतता का प्रमाण है। सरकार से सवाल पूछना, नीतियों का विरोध करना और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना नागरिक स्वतंत्रता का अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन लोकतंत्र की वास्तविक परीक्षा केवल इस बात से नहीं होती कि विरोध करने की कितनी स्वतंत्रता है, बल्कि इससे भी होती है कि उस स्वतंत्रता का उपयोग किस उद्देश्य, किस भाषा और किस पद्धति से किया जा रहा है। किसी आंदोलन का मुद्दा कितावा ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, यदि उसका नेतृत्व दिशाहीन हो जाए, भाषा उत्तेजक बन जाए और पद्धति हिंसा अथवा अराजकता की ओर बढ़ने लगे, तो उसका नैतिक आधार कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए आज देश के सामने प्रश्न केवल आंदोलनों का नहीं, बल्कि उनके चरित्र, विश्वसनीयता और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का भी है। दिल्ली में हाल के विरोध प्रदर्शनों और उन पर प्रशासन की सख्ती के बाद सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप ने एक बार फिर लोकतंत्र की सीमाओं और संभावनाओं पर बहस छेड़ दी है। एक ओर शांतिपूर्ण विरोध नागरिकों का अधिकार है, तो दूसरी ओर सार्वजनिक व्यवस्था, नागरिक सुरक्षा और कानून का पालन सुनिश्चित करना शासन का दायित्व है। इन दोनों के बीच संतुलन ही संवैधानिक लोकतंत्र की पहचान है। न तो सरकार को कानून-व्यवस्था के नाम पर नागरिक स्वतंत्रताओं के अनावश्यक दमन की छूट दी जा सकती है और न ही आंदोलनकारियों को लोकतांत्रिक अधिकारों की आड़ में सार्वजनिक जीवन को बाधित करने का असंमित अधिकार प्राप्त है। संविधान अधिकार देता है, लेकिन उन अधिकारों के साथ उत्तरदायित्व भी जोड़ता है। आज सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि जनांदोलनों की दिशा कौन तय कर रहा है? क्या आंदोलन वास्तव में जनसमस्याओं के समाधान के लिए खड़े हो रहे हैं, अथवा जनता के असंतोष को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का साधन बनाया जा रहा है? यह प्रश्न किसी एक दल या संगठन तक सीमित नहीं है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सामाजिक संगठन हों या जनसमूह, सभी को अपने आचरण की कसौटी संविधान, नैतिकता और जनहित को बनाना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है, कमियों को सामने लाता है और जनहित के मुद्दों को राजनीतिक विमर्श में स्थान देता है। लेकिन विपक्ष का दायित्व केवल विरोध करना नहीं, बल्कि वैकल्पिक दृष्टि प्रस्तुत करना भी है। यदि हर असहमति को सत्ता के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष में बदलने का प्रयास किया जाए, हर प्रशासनिक निर्णय को राजनीतिक षड्यंत्र बताया जाए और प्रत्येक जनसमस्या को व्यापक अव्यवस्था का प्रतीक बना दिया जाए, तो वास्तविक मुद्दे शोर में खोने लगते हैं। इसी तरह सरकार भी यदि आलोचना



को शत्रुता समझने लगे, तो लोकतांत्रिक संवाद की संभावनाएं संकुचित हो जाती हैं। आंदोलन की साख उसके मूल उद्देश्य एवं भरोसे से बनती है। जिस मुद्दे को लेकर लोग एकत्र होते हैं, उसकी स्पष्टता, तथ्यात्मक प्रामाणिकता और समाधान की दिशा आंदोलन की विश्वसनीयता निर्धारित करती है। जब मूल प्रश्न पीछे छूट जाता है और राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं अथवा वैचारिक टकराव केंद्र में आ जाते हैं, तब आंदोलन की ऊर्जा बिखरने लगती है। जनसमर्थन जुटाना और जनविश्वास अर्जित करना दो अलग-अलग बातें हैं। भीड़ किसी क्षणिक आक्रोश का परिणाम हो सकती है, लेकिन जनविश्वास निरंतर नैतिक आचरण और रचनात्मक कार्यों से अर्जित होता है। भारत का लोकतांत्रिक इतिहास इस संदर्भ में अनेक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। वर्ष 1974 का छात्र आंदोलन और लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व बताता है कि जनाक्रोश को रचनात्मक परिवर्तन की शक्ति में कैसे बदला जा सकता है। बिहार के छात्रों ने भ्रष्टाचार, महंगाई और शासन संबंधी समस्याओं के विरुद्ध आवाज उठाई थी। जयप्रकाश नारायण ने इस असंतोष को व्यापक सामाजिक और राजनीतिक सुधारों की दिशा देने का प्रयास किया। आज के आंदोलनों को इस ऐतिहासिक अनुभव से सीखना चाहिए। किसी भी आंदोलन की सफलता केवल इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि कितनी सड़कें बंद हुईं, कितने लोग एकत्र हुए या किनेने दिनों तक विरोध चला। उसकी

सफलता का वास्तविक पैमाना यह होना चाहिए कि उसने किस समस्या का समाधान प्रस्तुत किया, जनजीवन में क्या सकारात्मक परिवर्तन लाया और समाज में संवैधानिक चेतना को कितना मजबूत किया। वर्तमान समय में इंटरनेट मीडिया ने जनमत निर्माण की प्रक्रिया को पूरी तरह बदल दिया है। अब कोई घटना कुछ ही मिनटों में व्यापक बहस का विषय बन सकती है। यह लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि इससे आम नागरिकों को अपनी बात रखने और प्रशासन से जवाब मांगने का मंच मिला है। लेकिन यही माध्यम भ्रामक सूचनाओं, अधूरे तथ्यों, भावनात्मक अभियानों और अपुष्ट आरोपों को भी तेजी से प्रसारित कर सकता है। हैशटैग, वायरल वीडियो और ऑनलाइन समर्थन अपने आप में किसी आंदोलन की नैतिक प्रामाणिकता का प्रमाण नहीं हैं। किसी आरोप की गंभीरता का निर्धारण उसके प्रमाणों से होना चाहिए, उसकी लोकप्रियता से नहीं। यदि आंदोलनकारी तथ्यों की पुष्टि किए बिना आरोप लगाते हैं, तो वे अपने ही उद्देश्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार प्रशासन का दायित्व है कि वह आलोचनात्मक आवाजों को केवल इसलिए संदिग्ध न माने कि वे सरकार के विरुद्ध हैं। पारदर्शिता, तथ्यपरक संवाद और निष्पक्ष जांच ही अविश्वास को दूर करने के प्रभावी उपाय हैं। आज युवाओं के पास डिजिटल तकनीक, नवाचार, उद्यमिता और सामाजिक सहभागिता के अनेक अवसर हैं। उनकी ऊर्जा केवल विरोध तक सीमित न रहे, बल्कि समाधान निर्माण में

भी लगे। भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन हो तो पारदर्शिता के व्यावहारिक उपाय सामने आएँ, चुनावी सुधारों की मांग हो तो प्रमाण आधारित सुझाव प्रस्तुत किए जाएँ, प्रशासनिक अन्याय का प्रश्न हो तो कानूनी और संस्थागत रस्तों को मजबूत किया जाए। विरोध की सार्थकता तब बढ़ती है, जब वह किसी बेहतर व्यवस्था की कल्पना और निर्माण का आधार बनता है। जनांदोलनों के संदर्भ में विदेशी शक्तियों की भूमिका पर भी चर्चा होती रही है। यह स्वाभाविक है कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में राष्ट्रीय हितों, बाहरी प्रभावों और सूचना के प्रवाह को लेकर सतर्कता बरती जाए। लेकिन इस विषय पर भी भावनाओं अथवा आशंकाओं के बजाय प्रमाणों के आधार पर बात होनी चाहिए। किसी आंदोलन में सरकार की आलोचना होने मात्र से उसे विदेशी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार यदि किसी गतिविधि में विदेशी वित्तपोषण, भ्रामक प्रचार अथवा अनुचित हस्तक्षेप के विश्वसनीय प्रमाण मिलते हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा केवल कठोर प्रशासनिक कार्रवाई से नहीं होती। वह नागरिकों के विश्वास, संस्थाओं की निष्पक्षता, न्याय की उपलब्धता और शासन की पारदर्शिता से मजबूत होती है। देश की आलोचना और देश के प्रति शत्रुता में अंतर समझना आवश्यक है। सरकार की किसी नीति का विरोध करना राष्ट्रविरोध नहीं है, जैसे राष्ट्रीय हित की चिंता करना किसी नागरिक की लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को सीमित करने का औचित्य नहीं बन सकता। अंततः लोकतंत्र की शक्ति न तो केवल सत्ता में निहित है और न ही केवल सड़क पर उतरने वाली भीड़ में। उसकी वास्तविक शक्ति नागरिक विवेक, संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता और समाज की संवाद करने की क्षमता में है। किसी भी आंदोलन को स्वयं से तीन प्रश्न अवश्य पूछने चाहिए-क्या हमारा मुद्दा तथ्यपरक और जनहितकारी है? क्या हमारी पद्धति लोकतांत्रिक और अहिंसक है? क्या हमारे प्रयास से समस्या का समाधान निकलेगा या समाज में विभाजन और अविश्वास बढ़ेगा? केवल मुद्दा सही होना पर्याप्त नहीं है, उसके लिए सही नेतृत्व, सही भाषा, सही पद्धति और सही लक्ष्य भी आवश्यक हैं। आंदोलन का उद्देश्य केवल किसी व्यवस्था को चुनौती देना नहीं, बल्कि उससे बेहतर व्यवस्था के निर्माण में योगदान करना होना चाहिए। जो आंदोलन समाज को विवेक, अनुशासन, न्याय और रचनात्मकता की दिशा देता है, वही इतिहास में स्थायी स्थान प्राप्त करता है। भारत का भविष्य ऐसे ही लोकतांत्रिक चिंतन में सुरक्षित है, जहां असहमति को सम्मान मिले, सत्ता जवाबदेह रहे, विपक्ष रचनात्मक बने और राष्ट्रहित का अर्थ नागरिक स्वतंत्रता तथा संवैधानिक मर्यादों के समन्वय में खोजा जाए।

फरियादियों की समस्याओं का समय पर करें निस्तारण : अस्मिता ममगाई

जयन्त प्रतिनिधि।कोटद्वार : पुलिस क्षेत्राधिकारी अस्मिता ममगाई ने कहा कि कोतवाली में अपनी समस्याएं लेकर आने वाले फरियादियों की शिकायतों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को गंभीरता से कार्य करना होगा। उन्होंने पुलिस कर्मियों को जनता के साथ मित्रवत व्यवहार रखने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे आमजन बिना किसी झिझक के अपनी समस्याएं पुलिस तक पहुंचा सकेंगे।

मंगलवार को क्षेत्राधिकारी अस्मिता ममगाई ने कोतवाली कोटद्वार का अर्द्धवार्षिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर का भ्रमण कर कार्यालय में रखे राजकीय एवं महत्वपूर्ण अभिलेखों का अवलोकन किया। उन्होंने सभी अभिलेखों को अद्यतन रखने के निर्देश दिए। इसके बाद मालखाना, बैरक, मैस, सीसीटीएनएस कक्ष और



कोटद्वार कोतवाली में निरीक्षण करती सीओ अस्मिता ममगाई

सीसीटीवी प्रणाली का निरीक्षण किया। मालखाने में रखी सरकारी संपत्ति, शख्ओं और कारतूसों का भौतिक सत्यापन किया गया। साथ ही पुलिस कर्मियों से शख्ओं की हथेलिंग का अभ्यास करवाकर उनकी तैयारियों को

परखा गया। क्षेत्राधिकारी ने आपदा प्रबंधन उपकरणों की स्थिति की जांच करते हुए उन्हें सदैव कार्यशील अवस्था में रखने के निर्देश दिए, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में उनका प्रभावी उपयोग किया जा सके।

निरीक्षण के बाद क्षेत्राधिकारी ने पुलिस कर्मिकों का सम्मेलन लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मी अपने-अपने बीट क्षेत्रों की समुचित जानकारी रखें और आमजन के साथ मुद्दु एवं शालीन व्यवहार बनाए रखें। जन-पुलिस समन्वय को मजबूत बनाने के लिए भी गंभीरता से प्रयास किए जाएं। उन्होंने साइबर अपराधों, महिला संबंधी अपराधों और अन्य महत्वपूर्ण कानूनों के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस कर्मियों से जनहित से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करने और फरियादियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने को कहा। क्षेत्राधिकारी ने स्पष्ट किया कि पुलिस की कार्यप्रणाली ऐसी होनी चाहिए, जिससे आमजन का पुलिस पर विश्वास बढ़े और पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके।

राम वनवास की लीला देख भावुक हुए दर्शक

श्रीराम के राज्याभिषेक की खुशी मातम में बदली

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : कलालघाटी स्थित ओकराखर एवं दशहरा कमेटी के तत्वावधान में आयोजित रामलीला मंचन के छठें दिन भगवान श्रीराम के राज्याभिषेक की घोषणा, कैकेयी संवाद और राम वनवास की लीलाओं का मंचन किया गया। श्रीराम को 14 वर्ष का वनवास मिलने के दृश्य ने दर्शकों को भावुक कर दिया।रामलीला में दशरथ दरबार में भगवान श्रीराम के राज्याभिषेक की घोषणा होते ही पूरी अयोध्या उत्सव में डूब गई। चारों ओर प्रसन्नता और उल्लास का माहौल था। राजतिलक की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन कैकेयी के कोप भवन में जाने और राजा दशरथ से अपने दो वरदान मांगने के प्रसंग ने माहौल बदल दिया। कैकेयी संवाद के बाद श्रीराम को 14 वर्ष का वनवास मिलने की लीला का मार्मिक मंचन किया गया। श्रीराम के वन जाने के प्रसंग ने दर्शकों को

संक्षिप्त समाचार तीन दिवसीय प्रशासनिक प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : विकास भवन सभागार में डॉ. रघुनंदन सिंह टेलिया प्रशासनिक अकादमी (एटीआई), नैनीताल के सहयोग से तीन दिवसीय प्रशासनिक प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू हुई। इस मौके पर एटीआई नैनीताल के अपर कार्यक्रम निदेशक अनूप बमोला ने कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत की। कार्यशाला के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 और लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम पर प्रशिक्षण दिया गया। 14 अक्टूबर को पदोन्नति, चयन वेतनमान, वेतन निर्धारण, समयमान वेतनमान, एसीपी और एमएससी से संबंधित जानकारी दी जाएगी। वहीं 15 को आपदा प्रबंधन और इंसीडेंट रिसॉन्स सिस्टम (आईआरएस) पर क्षमता विकास प्रशिक्षण होगा। सीडीओ अशोक जोशी ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम कर्मिकों को नियमों और प्रक्रियाओं की बेहतर समझ देने के साथ कार्य क्षेत्र की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान खोजने में सहायक होते हैं। बीजीआर परिसर के विधि विभागाध्यक्ष डॉ. मुकेश रावत, अधिवक्ता रंजना डे, स्वजल परियोजना प्रबंधक दीपक रावत, परियोजना निदेशक विवेक उपाध्याय, डीएसटीओ राम सलौने, उखड़ा परियोजना प्रबंधक चंद्रप्रकाश उपाध्याय आदि मौजूद रहे।

रास्ते पर गड़्ढों ने बढ़ाई मुश्किलें स्थानीय लोगों ने की मरम्मत की मांग

उत्तरकाशी। मणिकर्णिका घाट तक जाने वाले मार्ग पर जगह-जगह गड़्ढे बने हुए हैं इससे स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

गंगोत्री धाम की यात्रा पर जाने से पहले श्रद्धालु बड़ी संख्या में मां गांग के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए यहां पहुंचते हैं, ऐसे में खराब रास्ते के कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने नगर पालिका से मार्ग को मरम्मत कराने के साथ ही घाट पर अन्य सुविधाएं दुरुस्त करने की मांग की है।जिला व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय प्रकाश बडोला ने बताया कि मणिकर्णिका घाट पर प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं। गड़्ढों की वजह से लोगों के पैर मुड़ने और चोटिल होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा आसपास के गांवों से देवघाटलियों के साथ सैकड़ों ग्रामीण गंगा स्नान के लिए भी घाट पर पहुंचते हैं। बावजूद इसके रास्ते की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस समस्या के बारे में नगर पालिका को मौखिक रूप से कई बार अवगत कराया जा चुका है लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है।

नचिकेता ताल के पर्यटन विकास को मिलेगी नई पहचान

उत्तरकाशी। जनपद की प्राकृतिक एवं पौराणिक धरोहर नचिकेता ताल को ईको टूरिज्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की कवायद तेज हो गई है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के निर्देशन में ताल के संरक्षण, पर्यटकों की सुरक्षा और आसपास के कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए कार्ययोजना पर काम किया जा रहा है। इसके तहत झील की परिधि में फुटपाथ और मजबूत रेलिंग का निर्माण कराया जा रहा है। जिला मुख्यालय से करीब 29 किलोमीटर दूर चारंगीखाल से तीन किलोमीटर पैदल मार्ग पर स्थित नचिकेताताल समुद्र तल से लगभग 2453 मीटर की ऊंचाई पर घने वन क्षेत्र के बीच बसा है।

जनसमस्याओं को लेकर उक्रांद ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान, आंदोलन की चेतावनी

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : लैंसडोन विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल (उक्रांद) ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जनसभाएं आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उक्रांद ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो व्यापक जनांदोलन शुरू किया जाएगा।उक्रांद नेता मुकेश बिष्ट और संदीप रैतेला के नेतृत्व में रिखणीखाल क्षेत्र के विभिन्न गांवों में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का गठन पहाड़ के बेहतर विकास और स्थानीय लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन आज भी पर्वतीय क्षेत्रों के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सुविधाओं के अभाव में लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वक्ताओं ने रिखणीखाल-धुमाकोट क्षेत्र में बढ़ते वन्यजीवों के आतंक पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जंगली जानवरों के हमलों से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। कुछ दिन पूर्व



रिखणीखाल क्षेत्र में उक्रांद की ओर से चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान के दौरान अपनी मांगों के समर्थन में हस्ताक्षर करते ग्रामीण।

भालू के हमलों में घायल एक महिला की मौत होने की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वन्यजीवों की बढ़ती सक्रियता के कारण ग्रामीणों का घरों से बाहर निकलना भी

मुश्किल होता जा रहा है।

रात के समय जंगली जानवर ग्रामीणों के आंगन तक पहुंच रहे हैं, जिससे विशेष रूप से बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। उक्रांद नेताओं ने कहा कि क्षेत्र की जनसमस्याओं को लेकर सरकार और संबंधित विभागों को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। उन्होंने बताया कि हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं को एकत्रित कर जापान राष्ट्रपति

योग प्रतियोगिता में मंजीत और आयुषी रही अख्ल चिन्यालीसौड़।

राजकीय महाविद्यालय चिन्यालीसौड़ में योग प्रतियोगिता एवं नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को योग के प्रति जागरूक करने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, नशे के दुष्प्रभाव के बारे में युवाओं को जागरूक करना था।

योग प्रतियोगिता के बालक वर्ग में बीए तृतीय सेमेस्टर के मंजीत पाल ने प्रथम, मयंक चौहान ने द्वितीय व अरुण रावत ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग में बीए पंचम सेमेस्टर की आयुषी राणा प्रथम, बीएससी पंचम सेमेस्टर की साक्षी द्वितीय व बीएससी तृतीय सेमेस्टर की अनामिका तृतीय स्थान पर रही। प्रतियोगिता के निर्णायक डॉ. अशोक कुमार अग्रवाल रहे। कार्यक्रम संयोजन योग प्रशिक्षक राजेश राणा एवं एंटी ड्रग्स सेल प्रभारी डॉ. अशोक कुमार अग्रवाल ने किया।

खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में 31 खाद्य पदार्थ अधोमानक, 145 की मौके पर हुई जांच

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के माध्यम से कुल 145 खाद्य पदार्थों की मौके पर जांच की गई, जिनमें से 31 खाद्य पदार्थ अधोमानक पाए गए।हालांकि, जांच में कोई भी खाद्य पदार्थ मानव उपयोग के लिए असुरक्षित नहीं पाया गया।

जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में डिप्टी कमिश्नर लैब वीरेंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में 12 और 13 अक्टूबर को खाद्य पदार्थों की जांच की गई। इस दौरान दूध एवं दूध पदार्थों के 21, मिठाई के 42, ऑयल एंड फैट के 15, मसालों के 33, सीरियल एवं सीरियल

प्रोडक्ट के 14 तथा अन्य श्रेणियों के 20 खाद्य पदार्थों की जांच की गई। जांच में 31 खाद्य पदार्थ अधोमानक पाए जाने पर विभागीय टीम ने संबंधित कारोबारियों को मौके पर ही आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए। विभाग का उद्देश्य त्योहारी सीजन में बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर निगरानी रखना और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है।

अभियान में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी कोटद्वार संदीप मिश्र, फूड एनालिस्ट जितेंद्र भंडारी, लैब असिस्टेंट गौरव नेगी सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। मुख्य तथ्य: 145 खाद्य पदार्थों की जांच में 31 अधोमानक मिले, जबकि कोई भी खाद्य पदार्थ मानव उपभोग के लिए असुरक्षित नहीं पाया गया।

मौनाक्षी ने द्वितीय, साक्षी, सोनाली एवं प्रिंसी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता महिला वर्ग में किरन नेगी, पुरुष वर्ग में आयुष नेगी विजेता रहे। वहीं, टेबल टेनिस प्रतियोगिता में कुमकुम विजेता रही। बालकों की 100 मी0 दौड़ में पवन कुमार प्रथम, आयुष नेगी द्वितीय एवं आयुष कुमार तृतीय स्थान पर रहे। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो. एल. आर. राजवंशी ने कहा कि विकसित भारत @2047 का संकल्प तभी साकार होगा, जब युवा पीढ़ी राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएगी। इस प्रकार की गतिविधियां विद्यार्थियों को केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से परिचित कराने के साथ-साथ उनमें सामाजिक उत्तरदायित्व, रचनात्मकता और राष्ट्रीय चेतना का विकास करता है। विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा का उपयोग समाज एवं राष्ट्र के विकास के लिए करना चाहिए। इस मौके पर रंगोली प्रतियोगिता संयोजक डॉ. अर्चना नौटियाल, क्रीड़ा प्रभारी अजय रावत आदि मौजूद थे।



दीदी योजना जैसी प्रमुख योजनाओं पर आधारित रंगोलियां बनाकर सामाजिक जागरूकता एवं राष्ट्र निर्माण

का संदेश दिया। प्रतियोगिता में मालती, अक्षिता एवं सलोनी ने प्रथम, अनामिका, सलोनी नेगी, ऋतिका एवं

चित्रकला-रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : सेवा संकल्प अभियान 2026-27 के अंतर्गत हमारे सपनों का भारत चित्र सेवा कार्यक्रम के तत्वावधान में विकसित भारत –2047 शीर्षक पर दिनांक 12.10.2026 को डॉ. पी. द. व. हि. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटद्वार में चित्रकला तथा रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया और सुंदर चित्रों की रचना की। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना तथा चित्रकला के माध्यम से भारत के प्रति उनके सपनों, विचारों, आकांक्षाओं एवं सामाजिक सरोकारों को अभिव्यक्त करने के लिए मंच प्रदान करना था।

कार्यक्रम के संयोजक डॉ. विनोद सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि चित्रकला केवल रंगों और रेखाओं का संयोजन नहीं, बल्कि विचारों, भावनाओं और सामाजिक चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति है। मेरे सपनों का भारत जैसे विषय विद्यार्थियों को राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य, सामाजिक समरसता,



पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत तथा राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों में छात्र-छात्राओं की सन्नित्र सहभागिता से उनमें कलात्मक अभिरूचि विकसित होने के साथ-साथ सकारात्मक सोच, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना भी सुदृढ़ होती है। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. (डॉ.) डी. एस. नेगी ने अपने

आशीर्वाचन में छात्र-छात्राओं की रचनात्मक सहभागिता की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अकादमिक ज्ञान प्रदान करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना भी है। कला विद्यार्थियों की संवेदनशीलता, कल्पनाशीलता और मौलिक चिंतन को विकसित करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा का निरंतर विकास करने तथा अपनी कला के माध्यम

से समाज और राष्ट्र के प्रति सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित किया।प्रतियोगिता के मूल्यांकन हेतु निर्णायक मंडल में डॉ. प्रवीण डोभाल, डॉ. मनीषा सिंह एवं डॉ. अंशिका बंसल सम्मिलित रहे। निर्णायकों द्वारा प्रतिभागियों की चित्रात्मक अभिव्यक्ति, विषय की प्रासंगिकता, मौलिकता, रचनात्मकता एवं रंग संयोजन जैसे विभिन्न पक्षों के आधार पर चित्रों का मूल्यांकन किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अविरति (बी.ए. प्रथम सेमेस्टर), द्वितीय स्थान श्रुबी (बी.कॉम. प्रथम सेमेस्टर) तथा तृतीय स्थान दिव्यांशी चौहान (बी.एससी. तृतीय सेमेस्टर) ने प्राप्त किया।

कार्यक्रम के माध्यम से छात्र-छात्राओं को अपनी कल्पनाशीलता और कलात्मक कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रतियोगिता में उनकी उत्साहपूर्ण सहभागिता ने कार्यक्रम को सफल बनाया। प्रतियोगिता ने कला के माध्यम से राष्ट्र निर्माण, सामाजिक चेतना और सकारात्मक परिवर्तन के संदेश को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करने की दिशा में सार्थक पहल की।



यमुनोत्री क्षेत्र के राना गांव में भरभराकर गिरा कुठार

उत्तरकाशी,यमुनोत्री क्षेत्र से लगे राना गांव में देर रात एक मकान का कुठार (अन्न भंडार) अचानक भरभराकर गिर गया।

यह कुठार मोहन सिंह पंवार का था। घटना के समय परिवार के सदस्य पास में बैठकर खाना खा रहे थे। अचानक कुठार गिरने से मौके पर अफरा-तफरी मच

गई। गनीमत रही कि पास में खाना खा रहे परिवार के सदस्य इसकी चपेट में आने से बच गए। सभी लोग बाल-बाल बच गए। घटना से परिवार के लोग सहम गए। कुठार गिरने से हुए नुकसान का विवरण फिलहाल उपलब्ध नहीं है। घटना के कारणों की भी जानकारी नहीं मिल पाई है।

बांध की झील में मछलियों के बीजों का किया संचय



(टिहरी)। मत्स्य विभाग ने जिला योजना के अंतर्गत आईटीबीपी के जवानों के साथ मिलकर टिहरी बांध की झील में करीब 3.50 लाख रोहू और कतला, नैना प्रजातियों की मछलियों के बीजों का संचय किया। प्रभारी सहायक निदेशक

मत्स्य आमोद नौटियाल ने बताया कि आने वाले समय में झील में मछलियों का बड़े स्तर पर उत्पादन होगा। अभी झील में गोल्डन महाशीर, कॉमन कार्प, स्नो ट्राउट, रोहू सहित कई प्रजातियों की मछलियों का उत्पादन किया जा रहा है।

इस मौके पर आईटीबीपी के डिप्टी कमांडेंट आशुतोष बिष्ट, जिला पंचायत उपाध्यक्ष मान सिंह शैतला, जिला पंचायत विजयपाल रावत, क्षेपंस अजय चंद्रा आदि थे।

राष्ट्रहित में योगदान देने के लिए किया प्रेरित

कर्णप्रयाग। डॉ. शिवानंद नौटियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सेवा संकल्प अभियान-विकसित भारत 2047 के तहत जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इसका लक्ष्य विद्यार्थियों व युवाओं में राष्ट्र निर्माण, सामाजिक सेवा व नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। जिपंड लक्ष्मण सिंह खत्री ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास के साथ राष्ट्रहित के कार्यों में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुभाष चमोला ने विद्यार्थियों को अनुशासन, सकारात्मक सोच और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने को कहा। इस अवसर पर प्राचार्य राम अवतार सिंह, नरेंद्र पंचाल, आशा डिमरी, छात्र संघ अध्यक्ष सुनील सिंह आदि मौजूद थे।

शिविर में 170 दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिक सहायक उपकरणों के लिए चिन्हित

जयन्त प्रतिनिधि। सतपुली : दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यकता के अनुरूप सहायक उपकरण उपलब्ध कराने एवं आवश्यक दस्तावेज तैयार करने के उद्देश्य से राजकीय इंटर कॉलेज सतपुली में विशेष शिविर आयोजित किया गया। जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग की ओर से एलियोको के सहयोग से आयोजित इस शिविर में कुल 170 दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण और चिन्हीकरण किया गया।

शिविर में एसडीएम सतपुली रेखा आर्य ने बताया कि 18 दिव्यांगजनों को एडिड योजना एवं 170 वरिष्ठ नागरिकों सहित राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए चिह्नित किया गया। लाभार्थियों की आवश्यकता के अनुसार आगामी प्रक्रिया पूरी कर उन्हें पात्रता के अनुरूप सहायक उपकरण



उपलब्ध कराए जाएंगे। शिविर में दिव्यांगजनों के दस्तावेज संबंधी कार्य भी किए गए। इस दौरान 18 दिव्यांगता प्रमाण-पत्र बनाए गए

तथा 30 यूडीआईडी कार्ड से संबंधित प्रक्रिया पूरी की गई, जिससे पात्र लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त

करने में सुविधा मिलेगी। एसडीएम रेखा आर्य ने बताया कि ऐसे शिविरों के माध्यम से दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को उनके क्षेत्र में ही आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसका उद्देश्य लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने के साथ-साथ सहायक उपकरणों के लिए चिह्नित करने और जरूरी दस्तावेज तैयार कराने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। शिविर में बीडीओ एकेश्वर सोरभ हांडा, बीडीओ कल्जीखाल चंद्र प्रकाश बल्लूनी, बीडीओ द्वारीखाल जयकृत सिंह बिष्ट, एडीओ समाज कल्याण कल्जीखाल राहुल राणा, एकेश्वर अमरीश सेनी, द्वारीखाल अंकित रावत, एडीओ पंचायत कल्जीखाल अरुण रावत, मंदीप रावत, अरविंद गुसाईं सहित पीएलवी जगमोहन डांगी, सज्जन सिंह नेगी, बबिता देवी, सुनील रावत, पीएलवी पुष्पेंद्र राणा आदि मौजूद थे।

एक नजर

बलाण गांव में चार साल बाद भी नहीं बना मोटर पुल

देवाल। ब्लॉक के बलाण गांव में पीएमजीएसवाई सड़क पर स्वीकृत मोटर पुल का काम चार साल बाद भी शुरू नहीं हो पाया है। यह पुल 2022 में स्वीकृत हुआ था लेकिन निर्माण कार्य अब तक अटका हुआ है। ऐसे में यहां गंदरे से आवाजाही होती है और बरसात में गंदरे का जलस्तर बढ़ने पर यातायात बाधित हो जाता है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से पुल का काम शीघ्र शुरू करने की मांग की।ग्राम प्रधान खीमी राम, बीडीसी सदस्य प्रदीप दानू, गोविंद बिष्ट, रणजीत सिंह और वीरेंद्र कुमार ने बताया कि बरसात में गंदरे का जलस्तर बढ़ने से गांव की आवाजाही ठप हो जाती है। कार्यदायी संस्था रूफ एंड ब्रिज ने पुल के एवेडमेंट का काम तक शुरू नहीं किया है। यह पुल हिमनी-बलाण सड़क पर बनाया था। वहीं रूफ एंड ब्रिज के प्रोजेक्ट मैनेजर मनीष राठौर ने कहा कि सड़क का लेबल उन्हा है। उसे नीचे करना पड़ेगा तभी पुल का निर्माण हो सकता है। बताया कि सड़क के लेबल को ठीक करने के लिए पीएमजीएसवाई के अधीक्षण अभियंता को पत्र लिखा गया है।

निर्माण के दो दिन बाद ही ढह गई दीवार

आदिबदरी। आदिबदरी कंवासेरा-थापली मार्ग पर 85 लाख रुपये की लागत से हो रहे ढामरीकरण और दीवार निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ गए हैं। खिल स्थान पर बनी एक दीवार निर्माण के दो दिन बाद ही ढह गई। सामाजिक कार्यकर्ता विजयेश नवानी ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब अन्य दीवारों के भी गिरने का खतरा बना हुआ है। नवानी ने पक्की चट्टान तोड़कर पथरों के उत्खनन पर भी चिंता जताई। उन्होंने लीनिवि से निर्माण कार्यों में मानकों का पालन सुनिश्चित करने और पथर निकालने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। वहीं लीनिवि के जेई अनुराग बेंजवाल ने कहा कि जल्द मौके का निरीक्षण करेंगे और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कोटी—रौल्यालूकी—बौरगांवी सड़क का निर्माण कार्य शुरू

लंबगांव (टिहरी)। प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र में कोटी—रौल्यालूकी से बौरगांव तक 500 मीटर मिंसिंग लिंक मोटर मार्ग का विधायक विक्रम सिंह नेगी ने शिलान्यास किया। 25.58 लाख रुपये की लागत से इस सड़क निर्माण किया जाएगा। विधायक नेगी ने कहा कि यह सड़क ग्रामीणों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके निर्माण से बौरगांव, उजाड़गांव, रतनी, कोटी और रौल्यालूकी सहित प्रतापनगर क्षेत्र के गांवों का लाभ मिलेगा।इस मौके पर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह रावत, ग्राम प्रधान सविता देवी, सीता देवी, विजयलाल, पूर्व प्रधान सुरेश राणा, बीडीसी सदस्य जसपाल नेगी, चंदन सिंह राणा, उमैद बुटोला आदि थे।

हड़ताल से कृषि ऋण और खाद बीज वितरण हो रहा प्रभावित

लंबगांव (टिहरी)। लंबित मांगों को लेकर साधन सहकारी समितियों के कर्मचारियों के हड़ताल से प्रतापनगर क्षेत्र में कृषि ऋण और खाद-बीज वितरण प्रभावित होने लगा है। समय पर ऋण नहीं मिलने और खाद-बीज वितरण में दिक्कतों के चलते किसानों की पेशानी बढ़ रही है। क्षेत्र की नौ साधन सहकारी समितियों में कामकाज प्रभावित होने से किसान जरूरी सेवाओं के लिए परेशान हैं।एमपेक्स कर्मचारी संगठन के आह्वान पर आंदोलनरत कर्मचारियों ने समान कार्य के लिए समान वेतनमान, गोल्डन जॉब योजना का लाभ, मिनी बैंक में ऋण वितरण की पारदर्शी व्यवस्था समेत विभिन्न मांगें उठाई हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से उक्त मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है।प्रतापनगर क्षेत्र की कुडियालगांव, मुखेम, दीनगांव, रौणद, सिलारी, कोटालगांव, लंबगांव, मांजफ और ल्वारखा साधन सहकारी समितियों में इन दिनों कामकाज बाधित है।

भालू के हमले में एक ही परिवार के चार लोग घायल

ज्योतिमठ। गोशाला में घुसे भालू ने हमला कर एक ही परिवार के चार लोगों को घायल कर दिया। शोर मचाने पर भालू वहां से भाग गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां से दो लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया।



नगर में भालू की दहशत बढ़ती जा रही है। मंगलवार तड़के करीब तीन बजे नगर के सिंहदरवार वार्ड में भालू ने एक गोशाला में घुसकर गाय को मार डाला। गाय की आवाज सुनकर पशुपाल गोशाला की तरफ आए। इसी दौरान उनका अचानक भालू से सामना हो गया और भालू ने उनपर हमला कर दिया। इसमें बिंदेश कुमार (37) का पैर, संतोषी देवी (26) का हाथ बुरी तरह जखमी हो गया जबकि भावना देवी और ओमप्रकाश भी घायल हो गए। परिवार के लोगों के शोर मचाने पर भालू वहां से भाग गया। सीएचसी ज्योतिमठ के प्रभारी डॉ. नीतम ने बताया कि बिंदेश और संतोषी देवी को

आक्रेश जताया। उन्होंने कहा कि भालू को जल्द पकड़ा जाए। इस दौरान नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की एसडीओ सुमन भी मौजूद रहीं। उन्होंने लोगों को क्षेत्र में रात बढ़ाने का भरोसा दिया। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के वन क्षेत्राधिकारी आशीष जीरवान ने बताया कि संभावित क्षेत्र में पिंजरा लगाया जाएगा और भालू को ट्रेंकुलाइज करने का प्रयास किया जाएगा।

डंपिंग ग्राउंड में मलबे के ढेर पर खेल रहे बच्चे

बड़कोट। नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 6 और 7 की तलहटी में स्थित डंपिंग ग्राउंड में सुरक्षा इंतजाम की कमी अब चिंता का विषय बनती जा रही है।

यहां मलबे के ढेर पर बच्चों के खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मलबे के खिसकने या बच्चों के फिसलकर गिरने की आशंका को लेकर स्थानीय लोगों ने संबंधित विभागों से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

स्थानीय निवासी बबिता देवी, मंगल सिंह, पूरन सिंह आदि का कहना है कि डंपिंग ग्राउंड में अनियंत्रित तरीके से मलबा डालने और उसका समुचित समतलीकरण

नहीं होने से स्थिति जोखिमपूर्ण बनी है। सुरक्षा कार्यों की धीमी गति भी लोगों की चिंता बढ़ा रही है। उनका मानना है कि यदि समय रहते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए, तो किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है। मंगल सिंह ने पुलिस प्रशासन, निर्माण कार्यदायी संस्था और बच्चों के अभिभावकों से मामले को गंभीरता से लेने को कहा है। साथ ही संबंधित एजेंसी से मलबे का समतलीकरण कराने और सुरक्षा संबंधी कार्य गुणवत्ता के साथ जल्द पूरा करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि बच्चों की सुरक्षा तय करना और संभावित दुर्घटना को रोकना प्राथमिकता होनी चाहिए।

मानकों पर खरे नहीं उतरे छह खाद्य पदार्थों के सैपल

नई टिहरी। टिहरी जिले के अलग-अलग बाजारों में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लिए गए छह खाद्य पदार्थों के नमूने प्रयोगशाला जांच में मानकों के विपरीत पाए हैं। इनमें दही के तीन, दूध, पनीर और मैदा के एक-एक नमूने शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से इन मामलों में छह खाद्य कारोबारियों के खिलाफ न्याय निर्णायक अधिकारी/ एडीएम की अदालत में वाद दायर किया गया है। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी शारदा शर्मा ने बताया कि अलग-अलग तिथियों में बाजारों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए अभियान चलाया गया था। इस दौरान भरे गए सैपलों को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया था। प्रयोगशाला जांच में छह नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे। संबंधित कारोबारियों को जांच रिपोर्ट पर अपना पक्ष रखने और उसे चुनौती देने का मौके दिया गया था। दो कारोबारियों की ओर



से अपील में प्रस्तुत तथ्य संतोषजनक नहीं पाए गए और उनकी अपील खारिज कर दी गई। सभी

छह मामलों में न्यायालय में अभियोजन की का- रेवाई शुरू कर दी गई है।

बीकेटीसी के अस्थायी कर्मचारी करेंगे आंदोलन

बदरीनाथ। बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों ने वन टाइम सेटलमेंट की मांग के लिए आंदोलन का एलान किया है। कर्मचारियों ने बीकेटीसी के बदरीनाथ के प्रभारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 14 अक्टूबर से ऋमिक अनशन का एलान किया।

बीकेटीसी के अस्थायी कर्मचारियों का कहना है कि बीकेटीसी के अंतर्गत वे 15-20 वर्षों से बदरीनाथ, केदारनाथ व अन्य अधीनस्थ मंदिरों में कार्यरत हैं। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री ने 11 अक्टूबर 2024 अगस्त्यमुनि में घोषणा की थी कि बीकेटीसी के सभी अस्थायी कर्मचारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट की व्यवस्था

लागू की जाएगी। सभी अस्थायी कर्मचारियों को समान कार्य का समान वेतन दिया जाएगा। मगर उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने एलान किया है कि 14 अक्टूबर से सभी कर्मचारी एक सप्ताह तक बदरीनाथ मंदिर के सिंहद्वार पर सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक ऋमिक अनशन करेंगे। उसके बाद भी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे। ज्ञापन भेजने वालों में रतनेश पंवार, संतोष पंत, कृष्णा, अमित बंदोलिया, राकेश सिंह, सतीश चंद्र, योगिता चौहान, शिवराज सिंह रावत, अर्पणा, हरीश सिंह, महावीर सिंह, दर्शन सिंह, दिनेश कोटियाल, योगंबर सिंह, अनूप आदि शामिल रहे।

खनन के विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन, रोका काम

आदिबदरी। सुगड़ गांव की महिला मंगल दल ने अवैध खनन के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिला मंगल दल ने सुगड़ बैंड-सिलपाटा मार्ग पर जेसीबी से पथर निकाल रहे एक ठेकेदार को काम करने से रोक दिया और उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

मंगलवार को सुगड़ बैंड-सिलपाटा मोटर मार्ग पर सुगड़ के पास एक ठेकेदार जेसीबी से चट्टानों को तोड़कर डंपरों में भर रहा था। इसकी भनक लगते ही गांव की 80 से अधिक महिलाएं खनन स्थल पर पहुंच गईं। उन्होंने जेसीबी और डंपर को घेरकर ठेकेदार के विरुद्ध नारेबाजी की। उन्होंने ठेकेदार को तब तक नहीं जाने दिया जब तक उसने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। महिला मंगल दल ने ठेकेदार को भविष्य में नन न करने की कड़ी चेतावनी दी और करीब 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। क्षेत्र पंचायत सदस्य सिलपाटा मुन्नी देवी और महिला मंगल दल अध्यक्ष सुगड़ सुशीला देवी ने बताया कि ठेकेदार इन पथरों को कंवासेरा थापली मार्ग



के दीवार निर्माण के लिए ले जा रहा था। इस और भुवन बरमोला आदि उपस्थित थे। वहीं लीनिवि गौचर के जेई अनुराग बेंजवाल ने

कहा कि हमारी ओर से कोई मशीन काम करने संबंधित सड़क पर नहीं गई। यदि कोई सड़क को नुकसान पहुंचा रहा होगा तो उस पर का- र्रवाई की जाएगी।

सोशल मीडिया पर भी दिखेगा गौचर मेला

कर्णप्रयाग। 14 नवंबर से 20 नवंबर तक होने वाले 74वें राजस्तरिय गौचर मेले को भव्य बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। एसडीएम और मेलाधिकारी अलकेश नौडियाल ने कहा कि इस बार गौचर मेला का सोशल मीडिया एकाउंट बनाया गया है।

इससे मेला सोशल मीडिया पर भी दिखाया जाएगा। इससे मेले की पहचान राज्यस्तर से राष्ट्रीय और विश्व स्तर तक होगी। बैठक में नया अध्यक्ष संदीप नेगी, सुनील पंवार, विधायक अनिल नौडियाल ने कहा कि समितियों में नाम लिखवाने तक ही जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए

इसके लिए काम करना जरूरी है। इससे मेले की कवायद शुरू हो गई है। इससे देश और विदेश में रह रहे प्रवासी भी गौचर मेले को देख सकेंगे। मंगलवार को गौचर नगर पालिका सभागार में आयोजित बैठक में मेले की 21 समितियों का पुनर्गठन किया गया। बैठक में विधायक अनिल नौडियाल ने कहा कि समितियों में नाम लिखवाने तक ही जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, प्रमुख दीपिका मैथुरी सहित कई लोगों ने अपने सुझाव रखे।

उत्तर और दक्षिण कोरिया में बढ़ा तनाव: किम जोंग उन ने दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें

सिओल , एजेंसी। उत्तर कोरिया ने सोमवार को अपने पूर्वी समुद्री इलाके की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। यह जानकारी दक्षिण कोरिया की सेना ने दिया। यह हाल के दिनों में हथियारों के प्रदर्शन का एक और मामला है, जिससे कूटनीतिक बातचीत लंबे समय से रुकी होने के बीच तनाव और बढ़ गया है।

जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने क्या बताया? – दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बताया कि मिसाइलें उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के आस-पास के इलाके से दागी गईं। हाल के वर्षों में देश ने अपने हवाई अड्डे का इस्तेमाल एक मुख्य लॉन्च साइट के तौर पर किया है। जॉइंट चीफ्स ने तुरंत यह नहीं बताया कि कितनी

मिसाइलें देखी गईं या वे कितनी दूर तक गईं। जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने कम से कम दो मिसाइलें देखीं और अनुमान लगाया कि ये हथियार देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन के बाहर समुद्र में गिरें।

दक्षिण कोरिया ने किया हथियार के उद्घान परीक्षण- यह लॉन्च दक्षिण कोरिया ने शुक्रवार को अपने पहले घरेलू स्तर पर विकसित हाइपरसोनिक हथियार के उद्घान परीक्षण के कुछ दिनों बाद किया। इस हथियार की ध्वनि की गति से कम से कम पांच गुना तेज उड़ने और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने इसे दक्षिण कोरिया की पारंपरिक रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।



उत्तर कोरिया क्यों कर रहा इतने परीक्षण?– सियोल के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए, उत्तर कोरिया अपने परमाणु-सक्षम हथियारों के जखीरे को बढ़ाने के लिए लगातार हथियारों का परीक्षण कर रहा है। इसमें 3 अक्टूबर को किया गया वह परीक्षण भी शामिल है, जिसे उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट-रेंज मिसाइल बताया था। इसे दक्षिण कोरिया और जापान की मिसाइल सुरक्षा प्रणालियों से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

उत्तर कोरिया ने मिसाइल के और भी टेस्ट किए हैं, लाइव-फायर ड्रिल की हैं और एक नया युद्धपोत भी शामिल किया है। नेता किम जोंग-उन अपने परमाणु

हथियार कार्यक्रम का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका और दक्षिण कोरिया के लंबे समय से रुके हुए कूटनीतिक बातचीत को फिर से शुरू करने के प्रस्तावों को भी ठुकरा रहे हैं।

दक्षिण कोरिया के तीन सैनिक कैसे घायल हुए? – पिछले महीने भारी हथियारों से लैस अंतर-कोरियाई सीमा के पास लैंड माइन धमाकों में दक्षिण कोरिया के तीन सैनिकों के घायल होने के बाद तनाव और बढ़ गया। दक्षिण कोरिया की सेना और अमेरिका के नेतृत्व वाली यूनाइटेड नेशंस कमांड ने निष्कर्ष निकाला कि ये धमाके उत्तर कोरिया की ओर से लगाए गए उपकरणों के कारण हुए थे। हालांकि, उत्तर कोरिया ने इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है

और माफ़ी की दक्षिण कोरिया की मांग का मजाक उड़ाया है।

हाल के वर्षों में, वॉशिंगटन के साथ परमाणु बातचीत में लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध के बीच, किम ने दक्षिण कोरिया के साथ सभी तरह की कूटनीति और सहयोग रोक दिया है और पड़ोसी देश को अपना पक्का दुश्मन बताया है। उन्होंने अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत फिर से शुरू करने की अपील को ठुकरा दिया है। 2019 में यह बातचीत टूट गई थी। उनकी सरकार की मांग है कि वॉशिंगटन प्योंगयांग के प्रति अपनी दुश्मनी वाली नीति छोड़े और बातचीत के लिए शर्त के तौर पर उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार खत्म करने की मांग को हटाए।

संक्षिप्त समाचार

भावनाओं को समझने में महिलाएं आगे, पर यही खूबी बन जाती है उनके लिए बड़ा बोझ

ज्यूरिख, एजेंसी। किसी बैठक में सहकर्मी का अचानक चुप हो जाना, किसी दोस्त के चेहरे से उसकी परेशानी भांप लेना या तनाव के बीच सही बात कहकर माहौल संभाल लेना। ये ऐसे कौशल हैं, जो रिश्तों को बेहतर बनाने के साथ कामकाज को भी आसान करते हैं।

लेकिन जब इन्हें किसी की स्वाभाविक खूबी मान लिया जाता है, तो यही क्षमता उसके लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी बन सकती है। महिलाओं के साथ अक्सर ऐसा ही होता है।

लिमरिक विश्वविद्यालय की मैरी एम हाउसफेल्ड और ज्यूरिख विश्वविद्यालय के योखेन मोंगेस ने 1995 से 2023 तक प्रकाशित शोधों की समीक्षा की। इसमें 76 देशों के छह लाख से अधिक लोग शामिल थे।



अध्ययन में औसतन महिलाओं का भावनात्मक बुद्धिमत्ता में प्रदर्शन पुरुषों से बेहतर पाया गया। यह बढ़त खास तौर पर दूसरों की भावनाओं को पहचानने, उनके कारण समझने और उनसे निपटने में मदद करने के मामले में दिखी। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं कि हर महिला इस मामले में हर पुरुष से बेहतर होती है। **बचपन से मिलता है** ज्यादा अभ्यास-भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और संभालने की क्षमता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक, इसकी एक वजह बचपन में लड़के-लड़कियों की परवरिश का अंतर हो सकता है। माता-पिता अक्सर बेटियों को भावनाओं पर बात करने और उन्हें शब्दों में व्यक्त करने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं, जबकि बेटों को कई बार भावनाएं दबाने की सीख मिलती है।

इस तरह लड़कियों को दूसरों की भावनाएं समझने और उनके अनुकूल प्रतिक्रिया देने का अधिक अभ्यास मिलता है। जैसे कोई भाषा या वाद्य यंत्र सीखने से उसमें दक्षता बढ़ती है, वैसे ही भावनात्मक कौशल भी अभ्यास से निखरते हैं। वर्ष 2019 में 58 अध्ययनों के मेटा-विश्लेषण में भी पाया गया कि प्रशिक्षण से भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित की जा सकती है। समस्या तब शुरू होती है, जब महिलाओं की इस क्षमता को कौशल मानने के बजाय उनकी स्वाभाविक जिम्मेदारी समझ लिया जाता है। दफ्तर में टीम का तनाव संभालना, परेशान सहकर्मी को सहारा देना और विवाद शांत करना अक्सर उन्हीं के हिस्से आता है। इससे कामकाज सुचारु रहता है, लेकिन प्रदर्शन के आकलन और पुरस्कारों में इस योगदान को जगह नहीं मिलती।

फिलीपीन में बच्चों के यौन शोषण का खौफनाक नेटवर्क, कैमरे के सामने परोसा जा रहा बचपन

मनीला/वॉशिंगटन, एजेंसी।

डिजिटल क्रांति के दौर में जहां दुनिया एक-दूसरे के करीब आई है, वहीं तकनीक का एक ऐसा घिनौना और खौफनाक चेहरा भी सामने आ रहा है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। द्वीपीय देश फिलीपीन में गरीबों का फायदा उठा मासूमों को बाल यौन शोषण सामग्री में बदला जा रहा है। उन्हें अपने देश में यौन शोषण का शिकार होना पड़ता है और अमीरों का शौक पूरा करने के लिए मीलों दूर स्थित शहरों में सीधे प्रसारित किया जाता है। सीएनएन की एक खोजी रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका और यूरोप जैसे अमीर देशों में बैठे लोग इसके बदले में बड़ी रकम खर्च करते हैं।

फिलीपीन इस अवैध और खौफनाक ऑनलाइन नेटवर्क का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। 13 वर्ष की केट (बदला नाम) की कहानी इस भयावह सच्चाई को बर्‍या करती है। कोविड-19 के दौरान जब केट के पिता की नौकरी चली गई और परिवार पाई-पाई को मोहताज हो गया तो



अपने ही कर रहे सौदा...एन्क्रिप्टेड एप्स से मिला बढ़ावा

बच्चों का सौदा करने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके अपने परिवार वाले ही होते हैं। फिलिपिनो पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार दलालों में बड़ी संख्या उन माताओं की है, जिन्होंने आर्थिक तंगी के आगे अपने बच्चों का सौदा कर दिया। बच्चों का शोषण करने वाले खरीदार समाज के हर वर्ग से आते हैं। इनमें कॉलेज के छात्र, बिजनेसमैन, रेस्टोरेंट कर्मचारी से लेकर जलवायु सलाहकार और पढ़े-लिखे पेशेवर तक शामिल हैं। कई आरोपी तो ऐसे हैं जो खुद शादीशुदा हैं और जिनके घर में बच्चे व नाती-पोते हैं। पहले यह धंधा डार्क वेब तक सीमित था लेकिन अब टेलीग्राम, व्हाट्सएप और वाइबर जैसे एन्क्रिप्टेड एप्स तक फैल चुका है। इंटरलीग्राम पर तो खुलेआम ऐसे प्राइवेट ग्रुप चलते हैं जहां कैडी, किड्डी जैसे सांकेतिक शब्दों का इस्तेमाल करके सामग्री की नुमाइश की जाती है।

पाकिस्तान को विश्व बैंक का झटका: दक्षिण एशिया की सूची से नाम बाहर, भारत से तुलना खत्म होने पर मचा बवाल

न्यूयार्क, एजेंसी। विश्व बैंक के क्षेत्रीय वर्गीकरण में बदलाव को लेकर पाकिस्तान में बहस छिड़ गई है। पाकिस्तानी पत्रकार शहबाज राणा के मुताबिक, पाकिस्तान को दक्षिण एशिया समूह से हटाकर मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले स्क्वड्रन समूह में शामिल किया गया है। हालांकि, इसे भारत की जीत या पाकिस्तान को दंडित करने का फैसला बताने के लिए ठोस प्रमाण सामने नहीं हैं। यह बदलाव विश्व बैंक की प्रशासनिक और क्षेत्रीय व्यवस्था से जुड़ा है।

विश्व बैंक के आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को 1 जुलाई 2025 से दक्षिण एशिया की श्रेणी से हटाकर मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्षेत्र में शामिल किया गया। इस बदलाव की पुष्टि विश्व बैंक के आँकड़ा पोर्टल और उसके दिसंबर 2025 के लेख में भी की गई है। दक्षिण एशिया के इस नए वर्गीकरण में अब भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव शामिल हैं।



पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग क्षेत्रीय समूह में रखा गया है। पाकिस्तानी पत्रकार शहबाज राणा ने अपने कार्यक्रम में इस बदलाव को भारत-पाकिस्तान तनाव और विश्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़ी परिस्थितियों से जोड़कर चर्चा की। उनके अनुसार, नई दिल्ली में कार्यालय होने की स्थिति में पाकिस्तानी अधिकारियों को वीजा संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था। क्षेत्रीय वर्गीकरण बदलने से पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति या उसकी आय के आधार पर तय होने वाली आर्थिक श्रेणी अपने आप नहीं बदलती।

सरकारी खजाने से ट्रंप का प्रचार पड़ा भारी जनता के पैसों से चल रहे विज्ञापनों पर कोर्ट ने लगाई रोक

वाशिंगटन एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने राजनीतिक संदेश के प्रचार के लिए सरकारी खजाने से चलाए जा रहे टीवी विज्ञापनों पर रोक लगानी होगी। न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत ने रविवार रात प्रशासन को आदेश दिया कि ऐसे सभी विज्ञापन तुरंत बंद किए जाएं, जो अब भी प्रसारित होने बाकी हैं। खास बात यह है कि प्रशासन पहले ही कह चुका था कि विज्ञापन अभियान जल्द खत्म होने वाला है। इसके बावजूद अदालत ने साफ कर दिया कि रविवार रात प्रसारित होने वाले विज्ञापनों समेत बाकी सभी विज्ञापनों को भी रद्द करना होगा।

जनता के पैसे से राजनीतिक प्रचार पर उठे सवाल- यह पूरा मामला उन टीवी विज्ञापनों से जुड़ा है, जिन पर करदाताओं के लाखों डॉलर खर्च किए गए। इन विज्ञापनों के जरिए ट्रंप के राजनीतिक संदेश को लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। इस खर्च पर सवाल उठाने हुए एक गठबंधन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। इस गठबंधन में गैर-दलीय निगरानी संगठन कॉमन कॉज भी शामिल था। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि सरकारी धन का इस तरह इस्तेमाल करना नियमों के खिलाफ



अब सरकारी खर्च और राजनीतिक संदेश के इस्तेमाल पर नजर

इस मामले ने सरकारी धन के इस्तेमाल और राजनीतिक प्रचार के बीच की सीमा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायत करने वाले संगठनों का कहना है कि जनता के पैसे का इस्तेमाल इस तरह नहीं किया जा सकता, जिसे वे किसी राजनीतिक संदेश को बढ़ावा देने का अनुचित तरीका मानते हैं। अदालत के आदेश का तत्काल असर यह है कि प्रशासन को बचे हुए विज्ञापनों को रोकना होगा। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, यह आदेश अस्थायी रोक के तौर पर जारी किया गया है। मामले में आगे क्या होता है, यह न्यायिक प्रक्रिया के अगले चरणों पर निर्भर करेगा।

अमेरिका-ब्रिटेन में पढ़ा रहे पाकिस्तानी शिक्षाविदों ने उठाई आवाज, इमान मजारी और उनके पति को रिहा करे पाकिस्तान

लंदन, एजेंसी। पाकिस्तान में वकील इमान जैनब मजारी-हाज़िर और हदी अली चड्ढा को हिरासत को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में कार्यरत पाकिस्तानी मूल के शिक्षाविदों ने आवाज उठाई है। उन्होंने दोनों वकीलों के खिलाफ आरोप वापस लेने और उन्हें तत्काल रिहा करने की मांग की है। शिक्षाविदों ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी और कानून के शासन से जुड़ा गंभीर मामला बताया है। लाहौर में जारी संयुक्त बयान में शिक्षाविदों ने पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के शासन की स्थिति पर चिंता जताई। यह बयान जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय के आकिल शाह की पहल पर जारी किया गया। बयान के मुताबिक, जनवरी 2026 में इमान मजारी और हदी चड्ढा को सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम कानून (पीईसीए) के तहत 17 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। इन पोस्ट में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों के



आलोचना की गई थी। शिक्षाविदों के अनुसार, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर 2026 को दोनों की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी थी। हालांकि, कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने एक अन्य मामले में उन्हें हिरासत में ले लिया। संयुक्त बयान के अनुसार, दोनों अब भी हिरासत में हैं। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि इमान मजारी जबर्न गुमशुदगी के मामलों पर आवाज उठाती रही है और पीड़ितों तथा उनके

परिवारों का प्रतिनिधित्व करती रही हैं। उन्होंने पाकिस्तान के ताकतवर संस्थानों की सार्वजनिक रूप से आलोचना भी की है। वहीं, हदी चड्ढा ने ईशान्दिा के आरोपों का सामना कर रहे लोगों और मृत्युदंड पाए कैदियों का बचाव किया है। बयान में कहा गया कि अपराधिक कानून का इस्तेमाल असहमति की आवाज दबाने या वकीलों को उनकी पैरवी के कारण डराने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

अमेरिका में राजनीतिक ताकत दिखाने की तैयारी, मिडटर्म चुनाव में क्यों बदला भारतीय-अमेरिकियों का प्लान?

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की भारत और प्रवासी भारतीयों के खिलाफ नीतियों ने राजनीतिक दमखम रखने वाले भारतीय प्रवासियों को नए सिरे से अमेरिकी सत्ता में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के पुरजोर प्रयासों के लिए प्रेरित किया है। इसलिए अब भारतीय-अमेरिकी केवल सांसद बनकर अमेरिकी सत्ता में हिस्सेदारी हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि तीन नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव में अपने मुद्दों के प्रति सहानुभूति रखने वाले अन्य उम्मीदवारों का भी समर्थन कर रहे हैं।

भारतीय-अमेरिकी समुदाय के नेताओं ने कहा कि कैलिफोर्निया और टेक्सास जैसे राज्यों में मजबूत मौजूदगी के बावजूद समुदाय के भीतर की प्रतिस्पर्धा के कारण निर्वाचित पदों



पर भारतीय प्रवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व कम रहा है। प्रवासी समुदाय के एक नेता ने कहा, ऐसे मौके आए हैं जब कई भारतीय-अमेरिकी एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ें हैं। इससे समुदाय के उम्मीदवारों की कम संख्या में जीत हुई।

उन्होंने राजनीतिक रूप से प्रसंगिक बने रहने के लिए एकजुटता पर जोर

दिया। कार्यकाल पूरा कर रही अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में भारतीय मूल के छह सदस्य हैं, लेकिन यह संख्या घटकर चार रह सकती है। इलिनोइस से राजा कृष्णमूर्ति और मिशिगन से श्री थानेदार प्राइमरी चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके।

भारतीय-अमेरिकी सांसद रो खन्ना (कैलिफोर्निया-17), प्रमिला जयपाल

(वाशिंगटन-7), एमी बेरा (कैलिफोर्निया-3) और सुहास सुब्रमण्यम (वर्जीनिया-10) फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। रिपब्लिकन विवेक रामास्वामी ओहायो के गवर्नर पद के चुनाव में मैदान में हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति के चार साल के कार्यकाल के बीच में होने वाले मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के सभी 435 सदस्यों और ऊपरी सदन सीनेट के 100 सदस्यों में से करीब एक-तिहाई का चुनाव होता है। इन चुनावों में कई राज्यों के गवर्नर व विधानसभाओं के साथ कुछ शहरों के मेयर और अन्य स्थानीय अधिकारियों के चुनाव भी शामिल होते हैं। नतीजे तय करते हैं कि कांग्रेस पर किस दल का नियंत्रण होगा और राष्ट्रपति की विधेयक पारित कराने की क्षमता पर भी उनका असर पड़ सकता है।



निखारें चेहरा

संवारेणें अपना भविष्य

पार्टियों में जाने के लिए किए जाने वाले मेकअप से लेकर कलाकारों के मेकअप तक इसकी उपयोगिता से सभी परिचित हैं, लिहाजा यह मेकअप करना शौक भी हो सकता है और एक कामयाब करियर भी । एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कुछ वर्ष पहले तक करियर के रूप में इसे अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था, लेकिन अब बाजार के बड़े-बड़े नामों ने इसमें सम्मान जोड़ दिया है । कुछ कामयाब नाम हैं- शहाना हुसैन, भारती तनेजा, वंदना लुथरा, ब्लॉसम कोचर, सिल्वी इत्यादि । इन्होंने मेकअप आर्टिस्ट के रूप में शुरुआत की और आज बिजनेस ब्रांड के रूप में पूरे देश में जाने जाते हैं । यही वजह है कि अब मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर करियर बनाने के इच्छुक युवा ट्रेनिंग लेने लगे हैं, ब्यूटी चैन में अच्छी जॉब उन्हें मिलने लगी है और कम पूंजी में खुद का व्यवसाय शुरू करने लगे हैं । आज मेकअप आर्टिस्ट सिर्फ फैशन मॉडल्स अथवा फिल्मी सितारों की ही जरूरत नहीं है । दूसरी जगहों पर भी इसकी खास डिमांड है । खासकर शादी के सीजन में इन लोगों की डिमांड बढ़ जाती है । अब तो इसमें भी स्पेशलाइजेशन हो गया है, जैसे कोई सिर्फ दूल्हे का मेकअप करता है तो कोई दुल्हन का । यहां आपको यह बता दें कि हर माध्यम के लिए अलग-अलग मेकअप होता है । टीवी/फिल्मी कलाकारों का मेकअप अलग होता है तो थिएटर में काम करने वालों का अलग । स्टेज आर्टिस्ट का मेकअप टीवी आर्टिस्ट की तुलना में चटक होगा । किसी कैरेक्टर को उसकी उम्र से अलग दिखाना है तो उसका मेकअप अलग होगा, वहीं जले या दाग दिखाने के लिए मेकअप अलग होगा । शहर और वहां की जलवायु के मुताबिक भी मेकअप किया जाता है । जैसे मुंबई में हवा में नमी रहती है, इसलिए पसीने को ध्यान में रख कर ऐसा मेकअप करना पड़ता है कि वह खराब न हो । वहीं राजस्थान में मेकअप के लिए अलग चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है । यह सभी संभव हैं, जब मेकअप आर्टिस्ट को इसका ठीक-ठीक ज्ञान हो कि स्थान, उम्र और जरूरत के लिहाज से कैसा मेकअप होना चाहिए ।

गुण क्या हो ?

इस प्रोफेशन में भी करियर बनाने के लिए कुछ विशेष गुणों की दरकार है । सबसे पहले उसमें विजुअलाइजेशन की क्षमता होनी चाहिए कि कौन सा स्टाइल या गेटअप किस पर फबेगा । उसे ऐसा रूप देना कि खुद को देख कर उसमें आत्मविश्वास भर जाए । कभी-कभी कई घंटों तक काम करना होता है, खासकर टीवी और फिल्म की शूटिंग के दौरान । शारीरिक और मानसिक रूप से उसका फिट होना बहुत जरूरी है, तभी वह अपने काम को सही-सही अंजाम दे पाएगा । आप में रंग और उसके असर की बारीक समझ होनी चाहिए । मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए आपका व्यवहार दोस्ताना होना चाहिए, तभी जिसका आप मेकअप करने जा रहे हैं, उसे बिना उबाए या थकाए उसका मनपसंद गेटअप आप उसे दे पाएंगे । इसके अलावा खुद भी आकर्षक दिखना जरूरी है । फैशन इंडस्ट्री में स्टाइल और ट्रेंड रोज बदलते हैं, इसलिए नई-नई तकनीक, हेयरस्टाइल्स और कॉस्मेटिक प्रॉडक्ट के बारे में उसे अपडेट रहना होगा ।

योग्यता क्या हो ?

मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है और न ही किसी प्रकार की योग्यता की । इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने स्कूल या कॉलेज में कौन सा विषय लिया था । बस आप में इस काम के प्रति लगाव होना चाहिए । अगर ऐसा है तो आपके लिए करियर की राहें आसान हैं । अगर 10वीं या 12वीं पास हैं तो और भी बेहतर । इस फील्ड में करियर बनाने के लिए आप ब्यूटीकैयर के अंतर्गत अन्य विषयों जैसे ब्यूटीशियन, मैनिच्युरिस्ट, पैडिक्युरिस्ट, इलेक्ट्रोलॉजिस्ट व अरोमा थेरेपी विषयों में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं । इसके अलावा आप किसी संस्थान से भी प्रशिक्षण प्राप्त कर

मेकअप आर्टिस्ट किसी जवान इंसान को बूढ़ा बना देता है तो बूढ़े इंसान को जवान । यही नहीं, मेकअप में वो ताकत है, जो चरित्र के हिसाब से कलाकार का पूरा व्यक्तित्व बदल दे । सुंदर दिखने-दिखाने की चाहत व्यक्तिगत रुचि से लेकर व्यावसायिक कौशल तक फैली हुई है । यही कारण है कि मेकअप करना एक खास किस्म का हुनर है ।

सकते हैं । संस्थानों द्वारा संचालित कोर्सज के पाठ्यक्रम में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डाइट, सेल्समैनशिप व सैलून आर्गनाइजेशन से संबंधित थ्योरी पढ़ाई जाती है । वहीं प्रैक्टिकल वर्क के रूप में फेशियल, डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज, मेकअप व इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट सिखाया जाता है ।

नौकरी के अवसर

वर्तमान में फिल्म व टेलीविजन इंडस्ट्री में मेकअप व हेयर ड्रेसिंग एक्सपर्ट की मांग बढ़ती जा रही है । इन एक्सपर्ट्स को फिल्म इंडस्ट्री में आर्टिस्ट के नाम से जाना जाता है । बतौर फीलांस भी इसमें हैं ढेरों काम । फैशन आर्गनाइजर, ब्यूटी पार्लरों, सिलेब्रिटीज के लिए बड़े पैमाने पर काम है ।

वेतन

इस क्षेत्र में आने वाले को बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता । प्रशिक्षण और इंटरशिप के दौरान ही आपकी कमाई होने लगती है । शुरुआती सैलरी 8 से 10 हजार मिलती है, लेकिन 5 साल के भीतर आप हर महीने 30 हजार रुपये तक कमा सकते हैं । एक बार आपका नाम हो गया तो आकांक्षा ही सीमा है । कुछ कलाकार साल में 5 लाख रुपये या इससे अधिक भी कमा लेते हैं । वहीं दूसरी तरफ विज्ञापन एजेंसी द्वारा शुरू की गई कंपेन में एक दिन में ही आपकी कमाई 1500 से 3000 रुपये तक हो सकती है ।

कहां-कहां हैं मौके ?



फिल्म/ टीवी/ वीडियो/ रंगमंच/ फैशन/ विज्ञापन एजेंसियों में तो बेशुमार जॉब हैं ही, तेजी से खुल रहे न्यूज चैनलों में भी मेकअप आर्टिस्ट की डिमांड है । वर्तमान में फिल्म व टेलीविजन इंडस्ट्री में मेकअप व हेयर ड्रेसिंग एक्सपर्ट की मांग बढ़ती जा रही है । इन एक्सपर्ट्स को फिल्म इंडस्ट्री में आर्टिस्ट के नाम से जाना जाता है । फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि स्टूडियो की चकाचौंध लाइट में एक्टर का मेकअप कैसे किया जाता है । बतौर फीलांस भी इसमें हैं ढेरों काम । फैशन आर्गनाइजर, ब्यूटी पार्लरों, सिलेब्रिटीज के लिए बड़े पैमाने पर काम है ।



यूपीएससी हर साल सिविल सेवा में परीक्षा का आयोजन करता है । इनमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस पदों के लिए सबसे ज्यादा दावेदार होते हैं । इस परीक्षा को क्रैक कर आईएएस की तरह आईएफएस अफसर बनना भी बहुत बड़ी बात होती है । क्योंकि एक आईएएस जहां देश के अंदर कार्य करता है, वहीं एक आईएफएस ऑफिसर दूसरे देशों में देश का प्रतिनिधित्व करता है । इस आर्टिकल के माध्यम से आज हम जानेंगे कि आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए और इनका क्या काम होता है ।

कौन और कैसे बन सकते हैं आईएफएस ऑफिसर

आईएफएस स्तर का अधिकारी देश का प्रतिनिधित्व अनेकों अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करता है । इनका दायरा एक आईएएस ऑफिसर से बढ़ा होता है । क्योंकि जहां एक आईएएस जिले व देश तक सीमित होते हैं, वहीं एक आईएफएस देश स्तर पर अधिकारिक रूप में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और देशों के साथ काम करते हैं । इनके काम का असर सीधा देश पर पड़ता है । आईएफएस के लिए भी उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से होता है, लेकिन आईएफएस की मुख्य परीक्षा का सिलेबस अन्य परीक्षाओं से अलग होता है । आईएफएस में आपको अंग्रेजी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है क्योंकि एक आईएफएस ऑफिसर विभिन्न देशों के राजदूत, अधिकारी व नेताओं से बात करनी होती है तो इसके लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान और बोलचाल में जरूरत होती है ।

एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

राष्ट्रीयता

आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए उम्मीदवार की राष्ट्रीयता निम्नलिखित होनी चाहिए

- भारत के नागरिक हो
- नेपाल/भूटान की नागरिक हो
- वे तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी, 1962 से पहले स्थायी रूप से बसने के लिए यहाँ आए, या
- भारतीय मूल के वे लोग जिन्होंने भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए युगांडा, बर्मा, पाकिस्तान, जांबिया, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, मलावी, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, जायरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रवास किया ।

शैक्षणिक योग्यता

- उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होनी चाहिए या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए ।

आयु सीमा

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आधिकारिक अधिसूचना में यूपीएससी आयु सीमा 2022 की जानकारी जारी की गई है । आयु सीमा पात्रता मानदंड के अनुसार, 1 अगस्त 2022 को 21 से 32 वर्ष के बीच की आयु के लोग यूपीएससी एग्जाम में आवेदन पत्र भर सकते हैं । आरक्षित वर्ग के आवेदक यूपीएससी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आयु में छूट के पात्र होते हैं ।



- एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए- 5 साल
- ओबीसी उम्मीदवारों के लिए- 3 साल ।
- जम्मू और कश्मीर राज्य के उम्मीदवार के लिए- 5 वर्ष
- रक्षा सेवा कर्मियों के लिए- 5 वर्ष
- पूर्व सैनिक जिनमें कमीशन अधिकारी और ईसीओ/एसएससीओ शामिल हैं, जिन्होंने कम से कम 5 साल की सैन्य सेवा प्रदान की है और उन्हें रिहा कर दिया गया- 5 वर्ष
- नेत्रहीन, मूक-बधिर और विकलांग व्यक्तियों के लिए- 10 वर्ष

उम्मीदवार कितनी बार दे सकते हैं ये एग्जाम

- सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार- 6 प्रयास
- एससी / एसटी के उम्मीदवार- कोई प्रतिबंध नहीं
- अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार- 9 प्रयास
- सामान्य व ओबीसी दिव्यांग- 9 प्रयास

मेडिकल स्टैंडर्ड

इस परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले आवेदकों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए । यूपीएससी सीएसई पर्सनालिटी टेस्ट के बाद चुने गए उम्मीदवार यूपीएससी द्वारा अधिसूचित चिकित्सा केंद्र में मेडिकल टेस्ट से गुजरते हैं । किसी भी सेवा में चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को सभी मेडिकल टेस्ट पास करना होता है ।

आईएफएस के कार्य

एक आईएफएस का काम उसके उसकी प्रोफाइल पर निर्भर करता है । विदेश में रह रहे भारतीयों की मदद वहां का भारतीय दूतावास करता है, जोकि एक आईएफएस का कार्य होता है । यही ऑफिसर राजदूत और राजनयिक के रूप में भी कार्य करते हैं । इनका मुख्य कार्य दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना और अन्य किसी प्रकार के वाद-विवाद को भी बातचीत के जरिए हल करना है । साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे यूनाइटेड नेशन व अन्य प्लेटफार्म आईएफएस अधिकारी ही विदेशी मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं । इसके साथ ही भारत की सुरक्षा व विदेशी नीति मामलों में भी इन्हीं आईएफएस की मदद ली जाती है और ये अपने अनुभव से देश की विदेश सुरक्षा पॉलिसी में अपने विचार व ज्ञान का उपयोग करते हैं ।



ऑडियो इंजीनियरिंग नई पीढ़ी का उभरता हुआ करियर

एक समय ऐसा था, जब आवाज को उसके मूल रूप में ही रिकॉर्ड किया जाता था, परन्तु आज उसमें काफी हद तक बदलाव लाया जा सकता है । यह सब संभव हो पाया है ‘ऑडियो इंजीनियरिंग’ से । वैसे तो आवाज या म्यूजिक का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन 20 वीं शताब्दी तक आते-आते उसमें कई चीजें जुड़ गईं । ऑडियो इंजीनियरिंग, ऑडियो साइंस की ही एक शाखा है । इसमें साउंड के चर करन, रिकॉर्डिंग करने, कॉपी करने, एडिटिंग एवं मिक्सिंग करने, इलेक्ट्रॉनिक एवं मैकेनिकल उपकरणों द्वारा आवाज में उतार-चढ़ाव लाने संबंधी कार्य किए जाते हैं । यह पूरा कार्य पोस्ट प्रोडक्शन के अंतर्गत आता है । इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक मिक्सिंग बॉर्ड लगा होता है, जिससे रिकॉर्डिंग एवं एडिटिंग प्रक्रिया में साउंड इनपुट जैसे स्विच, डायल, लाइट्स एवं मीटर को नियंत्रित किया जाता है । यह कार्य ऑडियो इंजीनियर के जरिए संपन्न किया जाता है । कई बार इन्हें रिकॉर्डिंग इंजीनियर या साउंड इंजीनियर के नाम से भी जाना जाता है । ऑडियो इंजीनियरिंग नई पीढ़ी के लिए एक उभरता हुआ करियर है, जो भारत एवं विदेश दोनों जगह फिल्म, वीडियो प्रोडक्शन, साउंड ब्रॉडकार्टिंग एवं एडवर्टाईजिंग में संभावनाएं तलाशता है । इस फील्ड के लिए खुद से कमिटमेंट एवं इंटरेस्ट होना आवश्यक है ।

कालिफिकेशन

एक सफल ऑडियो इंजीनियर बनने के लिए ऑडियोग्राफी, साउंड रिकॉर्डिंग एवं ऑडियो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अथवा डिग्री कोर्स का होना आवश्यक है । वैसे तो इस फील्ड में किसी विशेष शैक्षिक योग्यता की दरकार नहीं होती, परन्तु ऑडियो इंजीनियरिंग में बैचलर अथवा पीजी डिग्री को वरीयता दी जाती है । जहां तक डिमांड की बात है तो ऑडियो इंजीनियर बनने के लिए फिजिकल अथवा मैस की आधारभूत जानकारी सहायक साबित होती है, जिसके दम पर वे रिकॉर्डिंग रूम में कई तरह की प्रतिध्वनि का आकलन कर सकते हैं । इसमें अधिक प्रैक्टिकल ज्ञान के आधार पर एक अच्छा ऑडियो इंजीनियर बना जा सकता है । जिन छात्रों के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एवं फाइन आर्ट की पृष्ठभूमि रही है, वे भी इस कोर्स के लिए उपयुक्त साबित हो सकते हैं । साथ ही उन्हें रिकॉर्डिंग उपकरणों जैसे मिक्सिंग कंसोल एवं माइक्रोफोन की जानकारी भी होनी चाहिए । इस कार्य में उन्हें डिजिटल ऑडियो स्टेशन, स्पीकर, एंप्लीफायर सहित कई अन्य म्यूजिक उपकरणों का प्रयोग करना पड़ता है ।

कोर्स डिटेल्स

ऑडियो इंजीनियरिंग में साउंड रिकॉर्डिंग, एडिटिंग एवं मिक्सिंग के तकनीकी एवं रचनात्मक पहलुओं का बारीकी से अध्ययन किया जाता है । इसमें अधिकतर कोर्स की शुरुआत ही साउंड एवं रिकॉर्डिंग, पोस्ट प्रोडक्शन एवं ब्रॉडकार्टिंग की आधारभूत थ्योरी एवं फिक्सेसी से की जाती है । इसके तकनीकी पहलुओं के अंतर्गत ही साउंड मिक्सिंग में स्पेशल इफेक्ट्स डाला जाता है । कोर्स के बाद छात्र रिकॉर्डिंग टूल्स, माइक्रोफोन के प्रयोग के बारे में अच्छी तरह से वाकफ हो जाते हैं । इसके अलावा ऑडियो राइटिंग, इलेक्ट्रॉनिक

ऑडियो इंजीनियरिंग भारत एवं विदेश दोनों जगह फिल्म, वीडियो प्रोडक्शन, साउंड ब्रॉडकार्टिंग एवं एडवर्टाईजिंग में संभावनाएं तलाशता है । इस फील्ड के लिए खुद से कमिटमेंट एवं इंटरेस्ट होना आवश्यक है ।

म्यूजिक, साउंड रिकॉर्डिंग, म्यूजिक बिजनेस, मल्टीट्रैक प्रोडक्शन आदि कई ऐसे एरिया हैं, जिन्हें ऑडियो इंजीनियरिंग के तहत शामिल किया जाता है ।

पर्सनल स्किल्स

एक ऑडियो इंजीनियर को टेक्निकल नॉलेज, इलेक्ट्रिकल एटीट्यूड, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल सिस्टम एवं इकिपमेंट की जानकारी होनी आवश्यक है । म्यूजिक प्रोडक्शन में टीम वर्क, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आपके काम को गति दे सकते हैं । आग्रता, धैर्य, अच्छी समझ, अच्छी लय की जरूरत, अच्छी रिश्ता जैसे गुण ऑडियो इंजीनियर के लिए आवश्यक हैं । साथ ही उसे रिकॉर्डिंग माध्यमों जैसे एनालॉग टेप, डिजिटल मल्टीट्रैक रिकॉर्डर एवं कंप्यूटर नॉलेज की जानकारी भी सहायता दिला सकती है ।

नौकरी के अवसर

इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए ऑडियो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री पहली सीढ़ी होती है । सफलतापूर्वक कोर्स करने के बाद म्यू, टेलीविजन, एडवर्टाईजिंग, मल्टीमीडिया संस्थान, ब्रॉडकार्टिंग, सीडी प्रोडक्शन आदि में जॉब पा सकते हैं । लेकिन एक ऑडियो इंजीनियर को जो फील्ड सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, वह म्यूजिक इंडस्ट्री है । इसमें प्रारंभ में रिकॉर्डिंग इंजीनियर के सहायक के रूप में करियर आरंभ कर सकते हैं । अपने अनुभव के आधार पर जल्द ही वे ऑडियो इंजीनियर के पद पर पहुंच सकते हैं । इसके अतिरिक्त माइक्रोफोन, रिकॉर्डर, मिक्सर एवं सॉफ्टवेयर, म्यूजिक एवं स्पीच में कई तरह के काम सामने आते हैं । साउंड, म्यूजिक, डायलॉग, स्पेशल इफेक्ट्स, म्यूजिक प्रोड्यूसर को भी स्पेशलाइजेशन के रूप में अपनाया जा सकता है । म्यूजिक प्रोड्यूसर बनने के बाद खुद का रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी शुरू किया जा सकता है । स्टूडियो स्थापित करने के अलावा ऑडियो इंजीनियर फीलांस के रूप में भी काम कर सकते हैं । ऑडियो इंजीनियरिंग का क्षेत्र काफी प्रतियोगी है । इसमें वही लोग सफल हो सकते हैं, जिनमें टैलेंट एवं विशेष गुण हैं ।

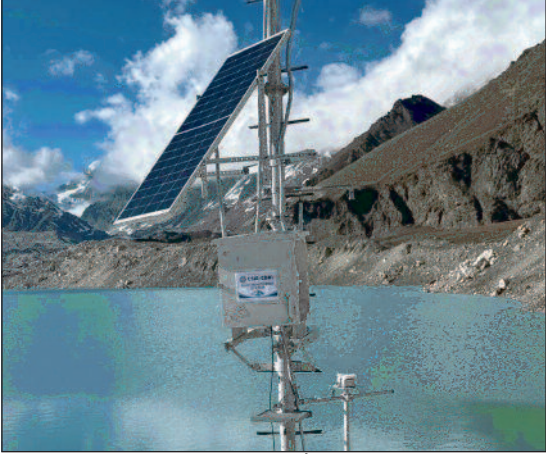
सेलरी स्ट्रक्चर

बतौर ऑडियो इंजीनियर इनकी सेलरी 10,000 रुपए प्रतिमाह से शुरू होती है तथा मान्यता मिल जाने के बाद इनकी सेलरी में तेजी से इजाजा होता है । तीन से चार साल के अनुभव के बाद इनकी सेलरी 30-35 हजार रुपए तक पहुंच जाती है । विदेशों में जॉब के अवसर मिलने के बाद सेलरी की कोई निश्चित सीमा नहीं होती ।



वसुंधरा ताल में पूर्व चेतावनी प्रणाली का पहला चरण सफल

देहरादून। उत्तराखंड में ग्लेशियल झीलों से उत्पन्न होने वाली संभावित आपदाओं के खतरे को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। चमोली जनपद स्थित वसुंधरा ताल में पूर्व चेतावनी प्रणाली (अल्टी वॉनिंग सिस्टम) स्थापित करने का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस अभियान के तहत झील और उसके आसपास अत्याधुनिक सेंसर स्थापित किए गए हैं। अभियान पूरा करने के बाद वैज्ञानिक एवं तकनीकी दल वापस लौट आया है। मंगलवार को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूपएसडीएमए) में सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने वैज्ञानिक दल का स्वागत किया। यह अभियान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक के निर्देशों पर संचालित किया गया। इसका उद्देश्य ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) यानी हिमनदीय झील के अचानक टूटने या पानी के तेजी से बाहर निकलने से उत्पन्न होने वाली



बाढ़ के जोखिम की निगरानी करना और समय रहते चेतावनी जारी करने की क्षमता विकसित करना है।

पहली बार ग्लेशियल झील में आधुनिक सेंसर आधारित निगरानी व्यवस्था
उच्च हिमालयी क्षेत्र की दुर्गम भौगोलिक

परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण मौसम के बीच वैज्ञानिकों ने वसुंधरा ताल में विभिन्न प्रकार के आधुनिक सेंसर स्थापित किए हैं। राज्य में किसी ग्लेशियल झील में इस तरह की पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित किए जाने को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। गौरतलब है कि 29 सितंबर को मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने अभियान दल को खाना किया था। दल ने कठिन परिस्थितियों में उपकरणों की स्थापना के साथ संचार प्रणाली का परीक्षण भी किया। इससे झील के जलस्तर, स्थानीय मौसम, बर्फ की स्थिति और आसपास होने वाली संभावित भू-गतिविधियों में बदलाव की निगरानी करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री और आपदा प्रबंधन मंत्री ने

जताई प्रसन्नता
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वसुंधरा ताल में पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना के प्रथम चरण की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में ग्लेशियल झीलों से उत्पन्न संभावित खतरे की समय रहते पहचान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक अनुसंधान और विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय से राज्य की आपदा प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह प्रणाली उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जोखिमों की निगरानी, समयबद्ध चेतावनी और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुस्था सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वहीं, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि वसुंधरा ताल में आधुनिक सेंसर आधारित निगरानी व्यवस्था की स्थापना राज्य के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे जलस्तर, मौसम, हिम की स्थिति और अन्य प्राकृतिक परिवर्तनों

से संबंधित आंकड़े प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने अभियान को सफल बनाने वाले वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों और सहयोगी सुरक्षा बलों के प्रयासों की सराहना की।
मुख्य सचिव बोले— आपदा पूर्व तैयारी को मिलेगी मजबूती
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कठिन परिस्थितियों के बीच पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करना वैज्ञानिक दक्षता, तकनीकी क्षमता और विभिन्न संस्थाओं के बीच प्रभावी समन्वय का उदाहरण है। सेंसर से प्राप्त आंकड़ों की नियमित निगरानी और वैज्ञानिक वीक्षणण के माध्यम से झील तथा उसके आसपास होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों को समझने में मदद मिलेगी।
सीबीआरआई और वाडिया संस्थान के वैज्ञानिकों की अहम भूमिका
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय ग्लेशियल

लेक आउटबर्स्ट फ्लड जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत यह अभियान संचालित किया। इसमें केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई), रड़की और वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, देहरादून के वैज्ञानिकों एवं तकनीकी विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूएसडीएमए ने अभियान के लिए आवश्यक समन्वय, लॉजिस्टिक सहायता और संचार उपकरण उपलब्ध कराए। अभियान में राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा।
कुलिंग गांव में 73.87 प्रतिशत मतदान हुआ
देवाल। त्रिस्तरीय पंचायत उप चुनाव के तहत कुलिंग ग्राम प्रधान का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। यहां 73.87 प्रतिशत मतदान हुआ। 14 को ब्लॉक सभागार में मतगणना होगी। सोमवार को कुलिंग ग्राम पंचायत में प्रधान पद पर चुनाव संपन्न हुआ।

उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, बारिश के साथ उंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार

देहरादून। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर कवच टूटने जा रहा है। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार, 14 से 16 अक्टूबर के बीच प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं, प्रदेश के उंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। मौसम में होने वाले इस बदलाव से पहाड़ों में ठंड बढ़ने और तापमान में गिरावट आने की संभावना है।
देहरादून समेत मैदानी जिलों में भी बारिश के आसार
मौसम निदेशक डॉ. सी.एस. तोमर के अनुसार, 14 और 15 अक्टूबर को देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार समेत प्रदेश के कुछ मैदानी जनपदों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा 15 अक्टूबर को गढ़वाल मंडल और 16 अक्टूबर को कुमाऊं मंडल के विभिन्न जनपदों में मौसम का प्रभाव देखने को मिल सकता है।



पिथौरागढ़ जनपदों में भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम में बदलाव के चलते पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड बढ़ सकती है, जबकि तापमान में भी गिरावट दर्ज होने के आसार हैं।

उंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना
मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, 14 अक्टूबर

को 3,800 मीटर से अधिक उंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। वहीं, 15 और 16 अक्टूबर को 3,500 मीटर से अधिक उंचाई वाले इलाकों में हिमपात होने की संभावना है। उंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी से मौसम का मिजाज और ठंडा हो सकता है। ऐसे में पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा करने वाले लोगों को मौसम की ताजा जानकारी लेकर ही सफर करने की सलाह दी जाती है।
मौसम में बदलाव को लेकर सतर्क रहने की जरूरत
अक्टूबर के मध्य में मौसम में संभावित बदलाव के मद्देनजर पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा करने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। मौसम संबंधी आधिकारिक अपडेट पर नजर रखना जरूरी है, ताकि बारिश और बर्फबारी के दौरान किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।

संक्षिप्त समाचार

स्थायीकरण की मांग के लिए क्रमिक अनशन शुरू

केदारनाथ/रूद्रप्रयाग। केदारनाथ मंदिर में तैनात अस्थायी वेतन कर्मियों ने वर्षों से लंबित मांगों का निस्तारण नहीं होने पर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। कर्मचारियों ने उन्हें स्थायी करने, आश्रितों को आर्थिक सहायता देने की मांग की और मंदिर समिति को इस संबंध में पत्र भेजा। केदारनाथ मंदिर परिसर में बैठे कर्मियों ने कहा कि क्रमिक अनशन अभी एक सप्ताह तक चलेगा। उन्होंने मांगें पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। पत्र में कर्मचारियों ने कहा कि बदरीनाथ—केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन करीब 300 अस्थायी कर्मचारियों दशकों से धामों में सेवाएं दे रहे हैं। मगर उन्हें स्थायी नहीं किया जा रहा है। उन्होंने सेवा के दौरान दिवंगत हुए करीब 12 कर्मचारियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। कहा गया है कि कर्मचारी एक सप्ताह तक प्रतिदिन पूर्वाह्न 11 से दोपहर एक बजे तक केदारनाथ मंदिर परिसर में क्रमिक अनशन करेंगे।

नेता प्रतिपक्ष के बयानों की भाजपाइयों ने की निंदा

नई टिहरी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल व पूर्व सेनाध्यक्ष बिपिन रावत पर दिए गए बयानों की भाजपाइयों ने निंदा की है। विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि राहुल गांधी को देश और एनएसए डोभाल से माफ़ी मांगनी चाहिए। पत्रकार वार्ता में विधायक उपाध्याय ने कहा कि एनएसए डोभाल और पूर्व सेनाध्यक्ष रावत ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। गत 12 वर्षों में डोभाल ने पूरी निष्ठा के साथ देश हित में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सुरक्षा में भी एनएसए डोभाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ऐसे लोगों का हमेशा सम्मान होना चाहिए। भाजपा जिलाध्यक्ष उदय रावत ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल ने निजी स्वाध्यों के चलते दोनों लोगों के प्रति अपमानजनक शब्द कहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड के गौरव और स्वाभिमान पर हमला किया है। इस मौके पर जिला महामंत्री बलवंत रावत, मंडल अध्यक्ष विजय कटैत, भाजयुमो जिलाध्यक्ष मनीष राणा, राजेंद्र डोभाल, अमर सिंह आदि मौजूद थे।

भाजपा ने राहुल गांधी के बयान की आलोचना की

रूद्रप्रयाग। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी के विरोध में भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने राहुल गांधी के बयान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अजीत डोभाल उत्तराखंड का गौरव हैं। ऐसे व्यक्तिव के खिलाफ टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के दौरान भी कांग्रेस ने सवाल उठाए और सबूत मांगे। उन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तान और आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस को इतनी परेशानी क्यों होती है। पत्रकार वार्ता में केदारनाथ विधायक अशा नौटियाल, जिला पंचायत सदस्य गंभीर सिंह बिष्ट, जिला पंचायत सदस्य अमित मैथ्यू और भाजपा जिलाध्यक्ष भारत भूषण भट्ट, मीडिया प्रभारी सतेंद्र बल्लाल आदि मौजूद रहे।

राहुल गांधी की डोभाल पर टिप्पणी उत्तराखंड का अपमान: नौटियाल

कर्णप्रयाग। क्षेत्रीय विधायक अनिल नौटियाल ने राहुल गांधी की एनएसए अजीत डोभाल पर की गई टिप्पणी को उत्तराखंड के गौरव और स्वाभिमान पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि यह टिप्पणी किसी व्यक्ति पर हमला नहीं है बल्कि उत्तराखंड को जन भावनाओं और स्वाभिमान पर आघात है। नौटियाल ने गौरव में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पर उत्तराखंड विरोधी होने का आरोप लगाया। इस अवसर पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अनूप नेगी, रानीगढ़ पट्टी मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र नेगी और नगर पालिका कर्णप्रयाग के अध्यक्ष गणेश शाह सहित अन्य नेता मौजूद थे।

देहरादून। उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में मेडिकल शिक्षा के बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जा रहा है। सरकार के बीते पांच वर्षों के कार्यकाल में तीन नए राजकीय मेडिकल कॉलेज शुरू हुए हैं। वहीं, रूद्रपुर में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज को भी जल्द 100 एमबीबीएस सीटों की अनुमति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे प्रदेश में मेडिकल पढ़ाई के अवसर बढ़ेंगे और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलने की संभावना है।

प्रदेश सरकार का लक्ष्य प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करना है, ताकि स्थानीय स्तर पर ही योग्य डॉक्टर तैयार किए जा सकें। इसके साथ ही उत्तराखंड के युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े और प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध हो सकें।

पांच वर्षों में तीन नए राजकीय मेडिकल कॉलेज शुरू
उत्तराखंड में देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार में छह राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। इनमें अल्मोड़ा,



पिथौरागढ़ और हरिद्वार के मेडिकल कॉलेज पिछले पांच वर्षों के दौरान शुरू किए गए हैं। इन संस्थानों के माध्यम से प्रदेश में एमबीबीएस की सीटों में वृद्धि हुई है और चिकित्सा शिक्षा के अवसरों का विस्तार हुआ है। इसके अलावा उधमसिंह नगर जिले के रूद्रपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वहां 100

एम्स में आरक्षित वर्ग के नर्सिंग अधिकारियों का कार्य बहिष्कार जारी

ऋषिकेश। एम्स में एम्स एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ से जुड़े नर्सिंग अधिकारियों का कार्य बहिष्कार दूसरे दिन भी जारी रहा। हालांकि एम्स प्रशासन से वार्ता का आश्वासन मिलने पर आंदोलित नर्सिंग अधिकारियों ने भूख हड़ताल शुरू नहीं की। एम्स प्रशासन पर पदेनव्रति प्रक्रिया में आसन्न गेस्टर लागू न किए जाने का आरोप लगाते हुए संगठन से जुड़े नर्सिंग अधिकारी डीपीसी निरस्त किए जाने और नई डीपीसी के लिए कमेटी गठित किए जाने की मांग कर रहे हैं। एम्स एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ से जुड़े करीब 300 से अधिक नर्सिंग अधिकारी सोमवार से कार्य बहिष्कार पर हैं। एएसएनओ प्रवीन भंडारी ने बताया कि एम्स प्रशासन ने एएसएनओ से एएसएस पदों पर पदेनव्रति के लिए बीते 10 अक्टूबर को डीपीसी आयोजित



की। लेकिन इस डीपीसी प्रक्रिया के दौरान आरक्षण रीसेट नहीं किया गया। जिससे आरक्षित वर्ग के करीब 53 नर्सिंग अधिकारी व 11 एएसएनओ पदेनव्रति से वंचित रह गए। भंडारी ने बताया कि

एम्स प्रशासन ने मंगलवार को वार्ता का आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक कोई वार्ता नहीं की गई है। आंदोलित नर्सिंग अधिकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की जाती आंदोलन जारी रहेगा। एम्स के पीआरओ डॉ.श्रीलाल मोहंती ने बताया कि आंदोलित नर्सिंग अधिकारियों से वार्ता की जा रही है। प्रयास है कि जल्द मामले को सुलझा दिया जाए।

डोईवाला महाविद्यालय में चार दिवसीय नाट्य कार्यशाला शुरू

डोईवाला। शहीद दुर्गामल्ल पीजी कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की और से महाविद्यालय में चार दिवसीय नाट्य प्रशिक्षण कार्यशाला प्रारंभ हो गई। कार्यशाला के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, संवाद कौशल और अभिव्यक्ति क्षमता को निखारने का प्रयास किया जाएगा। मंगलवार को महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. देवेश प्रसाद भट्ट के निदेशन में कलाशाला प्रारंभ की गई। संयोजक डॉ. शिव कुमार लाल ने बताया कि ड्रामा और थियेटर के माध्यम से विद्यार्थियों को मंच पर बोलने, चलने और अपनी बात को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत

नई टिहरी। भिलंगना ब्लॉक में उच्च शिक्षा के सीमित विकल्पों के कारण छात्रों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। रगड़ी (सांकरी) में राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की करीब तीन साल बाद भी स्थापना की प्रक्रिया ओर नहीं बढ़ पाई है। पांच माह पहले महाविद्यालय के लिए भूमि चिह्नित कर प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, लेकिन अभी तक स्वीकृति को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। भिलंगना ब्लॉक में वर्तमान में बालगंगा अशासकीय महाविद्यालय सेंदुल ही उच्च शिक्षा का एकमात्र संस्थान है, जहां घनसाली और ढुंगमंदार पट्टी के छात्र दूर-दराज के गांवों से पढ़ने पहुंचते हैं। सीमित संसाधनों के चलते कॉलेज में स्नातक

जयन्त

संस्थापक : नरेन्द्र उनीयाल
स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक नागेन्द्र उनीयाल
द्वारा प्रतिभा प्रेस बदरीनाथ मार्ग, कोटद्वार गढ़वाल (उत्तराखण्ड) से मुद्रित तथा बदरीनाथ मार्ग, कोटद्वार गढ़वाल (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित।
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र कोटद्वार, (गढ़वाल) उत्तराखण्ड होगा।
CONT. 9412081969
PRGI NO. 35469/79

संक्षिप्त

समाचार

डरबन टेस्ट

स्टीव स्मिथ को हेलमेट पर लगी चोट की जांच होगी



डरबन । ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को कनकशन अवलोकन किया जा रहा है। स्मिथ को दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिक नोर्तजे की गेंद से हेलमेट पर चोट लगी थी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डरबन में खेले जा रहे टेस्ट में स्मिथ को दूसरी पारी में बल्लेबाजी के दौरान एनरिक नोर्तजे का बाउंसर लगा था। स्मिथ की उम्मीद के मुताबिक नोर्तजे की गेंद नहीं उठी थी, गेंद देखकर वह झुकें थे, लेकिन गेंद सीधे उनके हेलमेट से जा टकराई थी। उस समय उन्होंने अपनी इनिंग सिर्फ चार गेंद खेली थी। उस समय उनके कनकशन की जांच की गई और उन्हें अपनी इनिंग जारी रखने की इजाजत दे दी गई। हालांकि, जब ऑस्ट्रेलिया ने फील्डिंग शुरू की तो स्मिथ वापस नहीं आए। उम्मीद है कि अगले 24 घंटों में उनके कनकशन की जांच होगी। चौथे दिन स्टैक्स के समय ब्यू वेबस्टर स्मिथ की फिटनेस के बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं कर पाए। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने उम्मीद जताई कि स्मिथ मंगलवार को मैदान पर उतर सकते हैं।

हरजिंदर कौर: कबड्डी छोड़ चुनी वेटलिफ्टिंग

नई दिल्ली । भारतीय महिला वेटलिफ्टिंग में हरजिंदर कौर का नाम काफी लोकप्रिय है। हरजिंदर ने लगातार दो कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए पदक जीते हैं। हरजिंदर कौर का जन्म 14 अक्टूबर 1996 को पंजाब के पटियाला



जिले में नाभा के पास मेहास में हुआ था। हरजिंदर का परिवार खेती से जुड़ा रहा है। शुरुआत में हरजिंदर कबड्डी खेला करती थीं और प्रशिक्षण के लिए प्रतिदिन 5 किलोमीटर साइकिल चलाकर सेंटर जाया करती थीं। परिवार की आर्थिक तंगी के कारण उन्हें प्रशिक्षण छोड़ना पड़ा। वेटलिफ्टिंग में हरजिंदर काफी देर से आईं। 2016 में पटियाला में पंजाबी युनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उन्होंने वेटलिफ्टिंग शुरू की। राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में दमदार प्रदर्शन के बाद हरजिंदर कौर को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला।

टी20 में फील्डिंग सुधारने के लिए टीम इंडिया के कल्चर में बदलाव जरूरी: आर श्रीधर

नई दिल्ली । भारत की सीनियर पुरुष टीम के पूर्व फील्डिंग कोच आर. श्रीधर मानते हैं कि टी20 फॉर्मेट में फील्डिंग के स्तर में आ रही गिरावट को ठीक करने के लिए राष्ट्रीय टीम को अपने कल्चर में पूरी तरह बदलाव की जरूरत है। श्रीधर ने यह भी कहा कि 22 अक्टूबर से शुरू होने वाले न्यूजीलैंड दौरे से पहले टीम में शामिल



नए खिलाड़ी फील्डिंग के मामले में पूरी तरह तैयार नहीं हैं। आंकड़ों के अनुसार, साल 2026 में टी20 मुकाबलों में भारत की फील्डिंग का स्तर गिरा है। केच पकड़ने की क्षमता के मामले में भारत टॉप 10 देशों में दूसरे-आखिरी स्थान पर है (73.4 प्रतिशत)। टीम ने चौकाने वाले 58 केच छोड़े हैं। भारतीय फील्डर्स ने भले ही 129 रन बचाए हों, लेकिन केच छोड़ने और ग्राउंड-फील्डिंग की गलतियों के कारण 226 रन अतिरिक्त बने, जिससे कुल मिलाकर 97 रनों का नुकसान हुआ।

शुभमन गिल और शेफाली वर्मा ने पुरुष और महिला वर्ग में

जीता आईसीसी ‘प्लेयर ऑफ द मंथ’ पुरस्कार



दुबई । भारतीय वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल और महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को सितंबर महीने के लिए पुरुष और महिला श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। यह तीसरी बार है जब भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेटर्स को एक साथ किसी महीने के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के तौर पर चुना गया है। गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद सितंबर महीने के लिए आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। गिल ने पांचवीं बार यह सम्मान हासिल किया है। उन्होंने पुरुष कैटेगरी में सबसे ज्यादा बार यह खिताब जीतने के अपने रिकॉर्ड को और आगे बढ़ाया है। शेफाली वर्मा ने विमेंस एशिया कप और एशियन गेम्स में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने के बाद दूसरी बार महीने के श्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। गिल को मिले इस नए अवॉर्ड ने उन्हें वेस्टइंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज के साथ खड़ा कर दिया है। मैथ्यूज ने भी पांच बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड जीता है। गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में 110 रन बनाए थे, जबकि दूसरे मैच में 133 गेंदों पर शानदार 223 रनों की पारी खेली थी। पुरस्कार जीतने के बाद गिल ने कहा, ‘अपना पांचवां आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड जीतकर बहुत अच्छा लगा रहा है। मैं इस सम्मान के लिए पैनल का शुक्रगुजार हूं। इतने रन बनाना बहुत अच्छा लगा और अपने

के अलावा भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा और जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा को नामित किया गया था, जबकि महिलाओं में शेफाली के अलावा श्रीलंका की कप्तान चमारी अथापट्टू और भारत की लेफ्ट-आर्म स्पिनर श्री चरणों को नामित किया गया था।



घरेलू फैस के सामने सफल रन चेज का हिस्सा बनना और भी खास था। जिनका सपोर्ट हमें हमेशा अतिरिक्त बूस्ट देता है।’ उन्होंने कहा, ‘वनडे क्रिकेट की गति काफी बढ़ गई है। आपको तुरंत सोचना होता है, कंडीशन का जल्दी से अंदाजा लगाना होता है और पिच और टारगेट की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालना होता है। अगले साल दक्षिण अफ्रीका में होने वाले आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के साथ, हम अपने स्तर को बेहतर करते रहने और आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम एक मजबूत और संतुलित टीम बनाने के लिए दृढ़ हैं।’ शेफाली वर्मा ने कहा, ‘आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड फिर से जीतना एक अविश्वसनीय सम्मान है। एशिया कप और एशियन गेम्स में हमारी जीत में अपना रोल निभाना बहुत अच्छा लगा, और यह अवॉर्ड जीतने से ये जीत और भी खास हो गई हैं।’

उन्होंने कहा, ‘मैं आने वाले महीनों को लेकर उत्साहित हूं। अगले साल फरवरी में होने वाली आईसीसी विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस जारी रखने का पक्का इरादा है। यह एक और टूर्नामेंट है, जिसका मुझे इंतजार है। वर्ल्ड कप जीतने की याद अभी भी बहुत ताजा और खास है। मैं अपनी धरती पर आईसीसी टूर्नामेंट के लिए मैदान पर वापस आने का इंतजार नहीं कर सकती।’

सितंबर की शॉर्टलिस्ट में पुरुषों की कैटेगरी में गिल

न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया-ए के शुरुआती दो मुकाबलों से

पंत बाहर, कुशाग्र को मौका मिला

नई दिल्ली। विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत लेफ्ट-साइड स्ट्रेन के कारण न्यूजीलैंड के आगामी दौर पर इंडिया-ए के शुरुआती दो मुकाबलों से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार कुशाग्र को शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने यह जानकारी सोमवार को दी। पंत का इस दौर पर खेलना उनकी फिटनेस पर निर्भर था। 1-4 अक्टूबर के बीच ईरानी कप में जम्मू-कश्मीर के खिलाफ ‘रेस्ट ऑफ इंडिया’ टीम की कप्तानी करते हुए उन्हें वायरल बुखार हो गया था। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि 29 वर्षीय पंत मेडिकल टीम की देखरेख में हैं और लिंकन में 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले तीसरे मैच में उनके खेलने पर फैसला बाद में लिया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘वह बीसीसीआई मेडिकल टीम की देखरेख में हैं और अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं। तीसरे मैच में उनके खेलने पर फैसला बाद में लिया जाएगा। पुरुष चयन समिति ने पहले दो मुकाबलों के लिए पंत की जगह कुमार कुशाग्र को चुना है।’

झारखंड के 21 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज कुशाग्र, ध्रुव जुरेल को कप्तानी वाली इंडिया-ए की टीम में शामिल हुए हैं। इस टीम में यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, केएल राहुल, आकिब नबी, मुकेश कुमार, आकाश दीप, मानव सुथार और वाशिंगटन सुंदर जैसे सितारे भी मौजूद हैं। कुशाग्र पुडुचेरी में ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ इंडिया-ए के रेड-बॉल मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं। उन्होंने पहले मैच में 113 और 46 रन बनाकर इंडिया-ए को जीत दिलाई थी।

इंडिया-ए की अपडेटेड टीम

ध्रुव जुरेल (कप्तान/विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पोंडवकल, रविचंद्रन स्मरण, वाशिंगटन सुंदर, आकिब नबी, आकाश दीप, अशुल कंबोज, मानव सुथार, मुकेश चौधरी, साई सुदर्शन, यश राठौड़, मुकेश कुमार और कुमार कुशाग्र। (विकेटकीपर) (पहले और दूसरे मैच के लिए)।



पाक टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका टीम का ऐलान

कुसल मेंडिस करेंगे कप्तानी

कोलंबो । पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। 15

सदस्यीय टीम की कप्तान कुसल मेंडिस संभालेंगे। यह पहला मौका है जब कुसल श्रीलंका टेस्ट टीम की कप्तानी करेंगे। मेंडिस को वनडे और टी20 टीम की कप्तान सौंपे जाने के बाद अब टेस्ट टीम की कप्तान सौंपी गई है। ऐसे में एक विकेटकीपर बल्लेबाज के साथ ही बतौर कप्तान भी उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मेंडिस को कप्तानी पिछले सप्ताह धनंजय डी सिल्वा के टेस्ट कप्तान का पद छोड़ने के बाद सौंपी गई है। डी सिल्वा जनवरी 2024 से इस फॉर्मेट में श्रीलंका की कप्तानी कर रहे थे। उन्होंने अगली पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपने की जरूरत बताई थी। श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) सिलेक्शन कमिटी ने गुरुवार को बोर्ड के मुख्यालय में हुई मीटिंग में मेंडिस की बतौर टेस्ट कप्तान नियुक्ति की। विकेटकीपर-बल्लेबाज को सबसे लंबे फॉर्मेट में काफी अनुभव है। वह 75 टेस्ट मैचों में 4,836 रन बना चुके हैं, जिसमें 10 शतक और 23 अर्धशतक शामिल हैं। मेंडिस को मध्य में श्रीलंका का वनडे और टी20 कप्तान बनाया गया था। उन्होंने वनडे कप्तान के रूप में चरित्र असलांका और टी20 में दानुस शनाका की जगह ली थी। टेस्ट कप्तान के तौर पर उनकी नियुक्ति अब उन्हें तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में कप्तान बनाती है।

एमएस धोनी में क्रिकेट बाकी

आईपीएल 2027 में खेलने का फैसला उनका होगा: सीएसके सीईओ विश्वनाथन

चेन्नई । आईपीएल की सफलतम फ्रैंचाइजी में से एक चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) के सीईओ काशी विश्वनाथन का मानना है कि पूर्व कप्तान एमएस धोनी में अभी क्रिकेट बाकी है। वह टीम के लिए एक

अभी भी एक खिलाड़ी हैं, आप जानते हैं।’ धोनी ने आईपीएल 2026 में एक भी मैच नहीं खेला था। वह 45 साल के हो चुके हैं। ऐसे में धोनी के आगामी सीजन में खेलने पर सवाल उठते रहते हैं।



आखिरी सीजन खेलने की पूरी कोशिश करेंगे। धोनी इंजरी की वजह से आईपीएल 2026 में एक भी मैच नहीं खेल पाए थे। चेन्नई में मीडिया से बात करते हुए विश्वनाथन ने कहा कि धोनी अगले सीजन में खेलेंगे या नहीं, यह फैसला फ्रैंचाइजी ने पूरी तरह उन पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा, ‘यह एक ऐसा सवाल है जो आपको उनसे पूछना चाहिए। मुझे भी उनसे पूछना होगा। जब वह चेन्नई आते हैं तो वह हमें अपने फैसले के बारे में बताते हैं। मुझे लगता है कि उनके सीएसके के लिए खेलते रहने के चांस हैं। वह

एमएस धोनी आईपीएल 2027 में सीएसके के लिए खेलेंगे या नहीं, इस पर टीम के पूर्व खिलाड़ी और दिग्गज बल्लेबाज सुरेश रैना ने कहा कि वह धोनी को एक और आईपीएल सीजन के लिए वापसी करते देखना चाहते हैं। चेपोंक में सीएसके के पारंपरिक लेप ऑफ ऑनर में धोनी के हिस्सा लेने के बाद, रैना ने कहा कि उन्होंने आईपीएल 2027 के लिए उनसे वापसी करने की गुजारिश की थी। रैना ने कहा, ‘मैंने उनसे कहा कि आपने आईपीएल 2026 को मिस कर दिया। यह नहीं गिना जाएगा।’

ब्रिस्बेन ओलंपिक 2032 की सीईओ सिंडी हुक अपना पद छोड़ेंगी

नई दिल्ली । ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स ऑर्गनाइजिंग कमिटी की सीईओ सिंडी हुक ने घोषणा की है कि वह अपने चार साल के कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने पर अपने पद से हट जाएंगी। हुक को फरवरी 2023 में नियुक्त किया गया था। उनका चार साल का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल की शुरुआत में खत्म होने वाला है। ऑर्गनाइजिंग कमिटी के मुताबिक, आने वाले महीनों में एक नई नियुक्ति की घोषणा होने की उम्मीद है। ऑर्गनाइजिंग कमिटी बोर्ड ने हुक के कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के बाद पद छोड़ने के फैसले को मान लिया है। ऑर्गनाइजिंग कमिटी के मुताबिक, ‘लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक से ठीक एक साल पहले एक आसान बदलाव सुनिश्चित करने के लिए और ब्रिस्बेन 2032 के अपने शुरुआती प्लानिंग और कैपेबिलिटी बिल्डिंग फेज से ऑपरेशनल, प्रोजेक्ट और इवेंट डिलीवरी के अगले महत्वपूर्ण फेज में जाने के लिए एक नए लीडर को बेटन



सौंपने का यह सही समय है।’ हुक ने एक बयान में कहा, ‘पिछले चार सालों में, मैंने वह सब कुछ हासिल किया है जिसकी हमने उम्मीद की थी और इस दौरान मुझे कई अद्भुत अनुभव हुए।’ ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक ऑर्गनाइजिंग कमिटी की सीईओ के तौर पर, सिंडी गेम्स के ऑर्गनाइजेशन के सभी पहलुओं को लीड करने के लिए जिम्मेदार थीं, ताकि एथलीट और दर्शकों के लिए एक शानदार अनुभव बनाया जा सके और ब्रिस्बेन, साउथईस्ट क्वींसलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक पॉजिटिव विरासत छोड़ी जा सके। उनकी जिम्मेदारियों में गेम्स की प्लानिंग, स्पॉन्सरशिप, टिकटिंग और मर्चेंडाइजिंग के जरिए राजस्व जुटाना, वेन्यू के ऑपरेशन को मैनेज करना, इवेंट सुरक्षा, वॉलंटियर रिक्रूटमेंट आदि शामिल हैं।

भारत बनाम वेस्टइंडीज: आईसीसी ने पॉवेल और रदरफोर्ड को फटकारा

खाते में डिमेरिट अंक भी जुड़ा

नई दिल्ली । भारत के खिलाफ शुक्रवार को रांची में खेले गए दूसरे टी20 मैच के दौरान ‘आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट’ तोड़ने पर वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों रोमन पॉवेल और शेरफेन रदरफोर्ड को आधिकारिक तौर पर फटकार लगाई गई। इसके साथ ही दोनों खिलाड़ियों के खाते में एक-एक डिमेरिट अंक भी जोड़ा गया। आईसीसी के अनुसार, पॉवेल को खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहायता कर्मियों के लिए आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.2 का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जो अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट के सामान या कपड़ों, मैदान के सामान या फ्रिक्स्वर और फिटिंग के दुरुपयोग से संबंधित है। पॉवेल को आउट होने के बाद अपने बल्ले से गेंद को दूर मारने के लिए सजा दी गई। यह घटना वेस्टइंडीज की पारी के छठे ओवर में हुई, जब भारत के तेज गेंदबाज मयंक यादव ने पॉवेल को बोल्ट कर दिया। वहीं, रदरफोर्ड ने आर्टिकल 2.8 का उल्लंघन किया, जो अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान अंपायर के फैसले पर असहमति



जताने से संबंधित है। रदरफोर्ड को मैच के दौरान अंपायर के फैसले पर असहमति जताने के लिए फटकार लगाई गई। पारी के 13वें ओवर के दौरान एक गेंद को रदरफोर्ड वाइड मान रहे थे, लेकिन उसे वैलिड करार दिए जाने के बाद कैरिबियन खिलाड़ी अंपायर पर आक्रामक रूप से चिल्लाए। दोनों खिलाड़ियों ने अपने-अपने अपराध स्वीकार करते हुए एमिरेट्स आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरीज के प्रकाश भट्ट द्वारा प्रस्तावित सजो को मान लिया, जिससे औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। आईसीसी ने यह भी पुष्टि की कि दोनों खिलाड़ियों के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक-एक डिमेरिट प्वाइंट जोड़ा गया है। 24 महीने की अवधि में यह दोनों का पहला अपराध था। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम करने के बाद भारत ने टी20 सीरीज का पहला मैच 8 विकेट से जीता, जिसके बाद रांची में खेले गए दूसरे मुकाबले को वेस्टइंडीज ने 6 विकेट से अपने नाम करते हुए सीरीज में 1-1 से बराबरी की।